राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 01 मार्च 2026 वर्ष-9,अंक-37 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पश्चिम बंगाल-फाइनल वोटर लिस्ट में 7.04 करोड़ से ज्यादा वोटर्स

■ 1.82 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल किए गए

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के बाद राज्य में वोटरों की संख्या 7.04 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अग्रवाल ने कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस में फॉर्म-7 के जरिए 5.46 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए और फॉर्म-6 और फॉर्म-6अ जमा करके 1.82 लाख से ज्यादा वोटरों को शामिल किया गया। CEO ने कहा कि... 60 लाख से ज्यादा वोटर अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में हैं, लेकिन उन्हें पोस्ट-रक्फइलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया गया है। रिवीजन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के निदेर्शों के अनुसार किया गया था। इससे पहले 16 दिसंबर को राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी। इसमें से बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए थे। बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट इससे पहले 14 फरवरी को पब्लिश की जानी थी। लेकिन कार्य पूरा ना होने के कारण इसे पहले 21 फरवरी और फिर 28 फरवरी किया गया।

होली से पहले रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर बढ़ी भीड़

■ नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। होली के नजदीक आते ही रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ बढ़ाना शुरू हो गई है। दूर-दराज से आकर दिल्ली में काम करने वाले लोग शनिवार से ही अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होने लगे हैं।इसको लेकर रेलवे ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैरिकेडिंग की गई है। जगह-जगह सुरक्षा के इंतजाम हैं। काउंटर बढ़ाकर लाइनें अलग-अलग कर दी गई हैं। यात्री आसानी से स्टेशन में प्रवेश कर पा रहे हैं। विशेष होल्डिंग एरिया और फर्स्ट एड बूथ बनाए गए हैं। साथ ही उत्तर रेलवे ने होली पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक विभिन्न तिथियों में संचालित होंगी। रेलवे के अनुसार, छपरा-आनंद विहार टर्मिनल और गोरखपुर-नई दिल्ली रूट पर 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन संख्या 05089/05090 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा के बीच सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी।

आंध्र प्रदेश: पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 20 की मौत

6 गंभीर घायल, धमाके की आवाज 5 किमी. दूर तक सुनाई दी

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में शनिवार को पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाका हो गया। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के समय यूनिट में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ब्लास्ट हुआ। धमाके इतना भीषण था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल

लोगों को अस्पताल भेजना शुरू किया। पुलिस अधिकारी ने बताया- धमाका इतना तेज था कि लाशें पास के धान के खेतों में जाकर गिरीं। हरे-भरे धान के खेतों के बीच डरावना मंजर देखने को मिला, जब स्थानीय लोग बाराकालू, यानी खाद की बोरियों से बनी चादरों में लाशें ले जाते दिखे। पुलिस ने पास के खेतों में बिखरे शरीर के हिस्सों का पता लगाने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। काकीनाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हॉस्पिटल में आए घायल 90 से 100 परसेंट तक जले हुए हैं। उनका इलाज जारी है। सीएम नायडू ने कहा, राहत और बचाव कार्यों पर सरकार नजर रख रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, जब धमाका हुआ उस समय पटाखा बनाने वाली इस फैक्टरी में करीब 20 लोग काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम नायडू ने दुख जताया

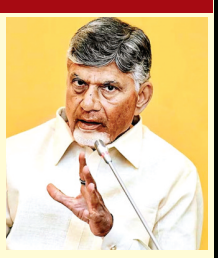

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी करने को कहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। राज्य की गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

गुजरात: पीएम मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया

कहा- देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा

साणंद (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) फैसिलिटी का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि 10-11 साल पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा कम होती थी। पहले देश की पहचान सॉफ्टवेयर के रूप में थी, आज भारत हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जाने लगा है। उन्होंने कहा- जून 2023 में MOU साइन हुआ, सितंबर 2023 में काम शुरू हुआ और फरवरी 2026 में यहां प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस सेक्टर को जानने वाले समझते हैं कि यह बहुत तेज रफ्तार है। साफ नीयत हो तो नीतियां भी साफ बनती हैं और फैसले जल्दी होते हैं। इस प्लांट में पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू होगा। यह केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट है। यह प्लांट 22,516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। माइक्रोन की ये फेसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी का प्रमाण है। अक और चिप जैसे क्षेत्र में हमारी साझेदारी अहम है। दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछली शताब्दी का रेग्युलेटर तेल था तो इस शताब्दी का रेग्युलेटर चिप होने वाली है। जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी तब भारत ने सेमिकंडक्टर की घोषणा की थी। कोरोना के समय लगा सब बिखर रहा है, लेकिन जो बीज हमने बोया उसका फल आज मिल रहा है। आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मेसेज है, इंडिया इज रेडी, इंडिया इज रिलायबल। मेक इन इंडिया अब फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। मैंने रतन टाट को मेसेज किया था, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट में देखिए एक गुजराती क्या कर सकता है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जो लाइफ चाहते हैं ये गुजरात है, ये वो भी बनाकर देगा, हम आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। गुजरात ने नीतियां बनाई उसका फायदा जमीन पर दिख रहा है।

एटीएमपी टेक्नोलॉजी पर आधारित है प्लांट

यह प्लांट एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) टेक्नोलॉजी पर आधारित है। प्लांट में सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उन पर जरूरी मार्किंग और फिर पैकेजिंग की जाएगी। इससे देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को मजबूती मिलेगी और देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब तक भारत माइक्रो चिप्स के मामले में आयात पर निर्भर रहा है। ऐसे में यह प्लांट देश में तकनीकी विकास, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। साथ ही, यह ह्यमेक इन इंडियाह्न और डिजिटल भारत जैसे अभियानों को भी गति देगा।

राहुल गांधी का वित्त मंत्री सीतारमण को लेटर

■ दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है। 25 फरवरी 2026 को लिखे लेटर में राहुल ने एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने और दिव्यांगता पेंशन पर लगाए गए नए आयकर प्रावधान को वापस लेने मांग की। राहुल ने लिखा है कि एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, लेकिन यह गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की सेवा की, वे आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस लेटर एक कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई है। दरअसल, राहुल गांधी डिफेंस की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। वे लगातार एक्स-सर्विसमेन के लिए सरकारी सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस फैसले का पूर्व सैनिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कदम सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करेगा, खासकर उन सैनिकों के लिए जिन्होंने चोट या दिव्यांगता के बावजूद सेवा जारी रखी और पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। विरोध करने वालों का तर्क है कि दिव्यांगता पेंशन राहत के रूप में दी जाती है, इसे आय नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए इस पर कर लगाना गलत है और इससे दशकों पुरानी परंपरा टूटती है। कांग्रेस ने 18 फरवरी को कहा था कि यदि सरकार ने सैनिकों के लिए दिव्यांगता पेंशन को आयकर की छूट से बाहर करने के अपने फैसले को 28 फरवरी तक वापस नहीं लिया तो वह पूर्व सैनिकों को साथ लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी।

नामीबिया, साउथ-अफ्रीका के बाद बोत्सवाना से आए 9 चीते, देश में कुनबा बढ़कर हुआ 48

श्योपुर (एजेंसी)। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार सुबह 9 और चीते लाए गए। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीता वायुसेना के विशेष विमान से पहले ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाए गए। कूनो में अब चीतों का कुनबा 36 से बढ़कर 45 गया है। गांधी सागर अभयारण्य के तीन चीतों को मिलाकर देश में 48 चीते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह विशेष विमान से ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पहुंचे। सुबह करीब 9:20 बजे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से क्रेट का

हैंडल घुमाकर दो चीतों को क्वारंटीन बाड़े में रिलीज किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई खेप में मादा चीतों की अधिक संख्या से कूनो में लिंगानुपात बेहतर होगा, जिससे भविष्य में प्राकृतिक प्रजनन की संभावनाएं और प्रबल होंगी। जानकारों के मुताबिक, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना के चीतों के शामिल होने से कूनो में जेनेटिक विविधता और मजबूत होगी। कूनो में अब वयस्क चीतों की संख्या में 18 मादा और 16 नर शामिल हैं। सभी 9 चीतों को अगले एक महीने तक विशेष क्वारंटीन बाड़ों में विशेषज्ञों और डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा जाएगा। तीन अलग-अलग देशों के चीतों का एक साथ होना इस प्रोजेक्ट की लंबी अवधि की सफलता के लिए निर्णायक साबित होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से लाए गए चीतों के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह बोत्सवाना और भारत के बीच जैव विविधता संरक्षण की एक ऐतिहासिक साझेदारी है।

केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अअढ सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। एक दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया था। कल शाम केजरीवाल ने अअढ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे AAP को हरा नहीं पाए तो खत्म करने जुट गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई, कोर्ट में ये साबित हो गया। दरअसल, आरोप है कि दिल्ली में 2021-22 की आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। केजरीवाल की सरकार के दौरान नई शराब नीति में लाइसेंस देने और मार्जिन तय करने में अनियमितताएं हुईं। इससे कुछ निजी कारोबारियों को फायदा पहुंचा। बाद में यह नीति वापस ले ली गई। उइक केस में आरोपियों को बरी किया गया है।

अमेरिका-इजराइल का ईरान पर हमला, 40 छात्राओं की मौत

ईरान ने भी इजराइल-दुबई पर मिसाइलें दागीं, कतर-यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक

तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत हो गई। जबकि 45 घायल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागीं हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने वअए के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। दरअसल, इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम 'लियोनस् रोर' (शेर की दहाड़) रखा है। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रम्प के मुताबिक, अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की।

खड़गे बोले: ईरान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। खड़गे ने कहा कि हालिया सैन्य घटनाक्रम के बाद मध्य-पूर्व की स्थिति बिगड़ रही है और ऐसे समय में शांति व स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने ईरान और अन्य मध्य-पूर्वी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही और सरकार से अपील की कि वह सभी जरूरी कदम उठाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।

काशी में जलती चिताओं की भस्म से होली

नरमुंड-चश्मा लगाकर आए संन्यासी, डमरू की थाप पर नाचे, 3 लाख टूरिस्ट पहुंचे

वाराणसी (एजेंसी)। जलती चिताएं, रोते-बिलखते लोग और चिता की राख से होली खेलते नागा साधु-संन्यासी। यह नजारा इस समय काशी के मणिकर्णिका घाट पर देखने को मिला। यहां शनिवार को मसाने की होली खेली गई। कोई गले में नरमुंडों की माला डाले था, तो कोई डमरू की थाप पर नाचता दिखाई दिया। घाट पर जश्न के बीच से शवयात्राएं भी गुजरती रहीं। रंग और चिता की राख में सराबोर होकर विदेशी पर्यटक भी झूमते नजर आए। शनिवार को मसाने की होली का रंगोत्सव डमरू वादन से शुरू हुआ। डमरू की गूंज के बीच

साधु-संन्यासी मणिकर्णिका घाट पहुंचे और पूजन किया। भस्म, रंग, गुलाल और अबीर बाबा मसान नाथ को अर्पित किए। इसके बाद भस्म की होली खेली। मसाने की होली खेलने के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचे थे। आमतौर पर जिस चिता की राख से लोग दूरी बनाते हैं, आज उसी राख में लोग श्रद्धा और आस्था के साथ सराबोर नजर आए। मणिकर्णिका घाट पर हर तरफ चिता भस्म की राख उड़ रही है। 'नमः पार्वती... हर-हर महादेव' और बम-बम भोले के जयकारे लगाते हुए संन्यासी होली खेलते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मणिकर्णिका घाट की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। रस्सी लगाकर पुलिसकर्मी तैनात हैं। इस दौरान लोगों की पुलिस से बहस हो गई। मणिकर्णिका घाट पर इस समय डमरू की धुन गूंज रही है। शरीर पर भस्म लपेटे कलाकार लगातार डमरू वादन कर रहे हैं। मसाने की होली के बीच मणिकर्णिका घाट पर पांडेयपुर निवासी दुर्गा देवी का शव अर्थी से गिर पड़ा।

6 महीने पहले से शुरू हो जाती है तैयारी

महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर होली के दौरान तरह-तरह की झांकियां भी निकाली जाती है। इसमें लोग भगवान शिव के बाराती की तरह शामिल होते हैं। कलाकार भूत, पिशाच, हाकिनी-डाकिनी, चुड़ैल के स्वरूप दिखते हैं। बाबा के बाराती नाचते-गाते रहते हैं। घाट पर धधकती चिंताओं के बीच में चिता भस्म होली की शुरूआत होती है। इस आयोजन की तैयारियां 6 महीने पहले से होती हैं। चिताओं की राख इकट्ठा की जाती है। जिसे भस्म के साथ होली के दिन उड़ाया जाता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बोतलबंद पानी का भारतः सार्वजनिक जल प्रशासन की गहरी विफलता

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है।

(लेखक- डॉ. सत्यवान सौरभ)

(भारत में पानी की प्यास केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि नीतिगत भी है।)

भारत में बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता केवल उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जल प्रशासन में व्याप्त गहरी और बहुस्तरीय प्रणालीगत समस्याओं की ओर भी स्पष्ट संकेत करती है। कभी जो नल का पानी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वही आज अविश्वास, असुरक्षा और असमानता का प्रतीक बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

आधुनिक भारत में जल संकट को अक्सर वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन या बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बोतलबंद पानी की लोकप्रियता का मूल कारण इनसे कहीं अधिक गहरा है। असल समस्या यह है कि नागरिकों का भरोसा सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणालियों से लगातार टूटता जा रहा है। नलों से आने वाले पानी की गुणवत्ता पर संदेह, नियमित आपूर्ति का अभाव, और पारदर्शिता की कमी ने लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर धकेल दिया है। जब राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, तब बाजार उस खाली स्थान को भर देता है—अक्सर मुनाफे की शर्तों पर।

शहरी भारत में बोतलबंद पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो यह लगभग जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़े जार और बोतलें आम दृश्य हैं। यह स्थिति विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शहरों में सबसे विकसित जल अवसंरचना होने का दावा किया जाता है। यदि इतनी सुविधाओं के बावजूद नागरिक सुरक्षित नल का पानी नहीं पी सकते, तो यह प्रशासनिक विफलता का सीधा प्रमाण है। पाइपलाइन की जर्जर हालत, सीवेज और पेयजल लाइनों का आपस में मिलना, तथा नियमित परीक्षण की कमी—ये सभी समस्याएँ वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन समाधान आधे-अधूरे ही रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग होते हुए भी उतनी ही चिंताजनक है। वहां बोतलबंद पानी का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे-जैसे ग्रामीण बाजारों तक निजी कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है, यह निर्भरता वहां भी बढ़ने लगी है। कई इलाकों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक या आयरन की अधिकता के कारण लोग स्थानीय जल स्रोतों से डरने लगे हैं। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सामुदायिक नल या हैंडपंप अक्सर या तो खराब रहते हैं या फिर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वे बोतलबंद पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब तबके दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। यह स्थिति जल के क्षेत्र में गहरी असमानता को जन्म देती है।

बोतलबंद पानी उद्योग का विस्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह उद्योग 'शुद्धता'' और 'सुरक्षा' का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन में गंभीर खामियां हैं। कई बार यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध बोतलबंद पानी भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद उपभोक्ता इसे नल के पानी से अधिक सुरक्षित मानते हैं। यह धारणा स्वयं में सार्वजनिक जल संस्थानों की साख पर सवाल है। यदि राज्य द्वारा प्रमाणित और नियंत्रित जल आपूर्ति प्रणाली पर नागरिक भरोसा नहीं करते, तो यह लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए भी खतरे की घंटी है।

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विरोधाभास नीति निर्माताओं की अल्पकालिक सोच को उजागर करता है।

सार्वजनिक जल प्रशासन की समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं हैं; वे संस्थागत और राजनीतिक भी हैं। जल प्रबंधन से जुड़े विभाग अक्सर संसाधनों की कमी, कुशल मानवबल के अभाव और आपसी समन्वय की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवा को राजनीतिक प्राथमिकता भी अक्सर नहीं मिलती। चुनावी घोषणाओं में बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं या स्मार्ट शहरों की बातें तो होती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जल आपूर्ति को सुधारने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं वर्षों तक अनसुलझी रहती हैं।

निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस संकट को गहरा कर रही है। जब सार्वजनिक प्रणालियाँ कमजोर होती हैं, तो समाधान के रूप में निजी कंपनियों को आगे लाया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इससे दक्षता बढ़ी है, लेकिन अक्सर इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो भुगतान कर सकते हैं। पानी जैसे आवश्यक संसाधन का बाजार आधारित वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बोतलबंद पानी इस निजीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्वच्छ पानी एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता वस्तु बन जाता है।

इस पूरी स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बोतलबंद पानी पर निर्भरता धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। लोग इसे समस्या के लक्षण के बजाय समाधान के रूप में देखने लगे हैं। इससे सार्वजनिक दबाव कम होता है और प्रशासनिक सुधार की मांग कमजोर पड़ जाती है। जब नागरिक स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, तो राज्य पर जवाबदेही का दबाव घट जाता है। यह चुपचाप स्वीकार की गई असफलता भविष्य में और बड़े संकटों को जन्म दे सकती है।

आवश्यकता इस बात की है कि जल को फिर से सार्वजनिक भलाई के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए सबसे पहले नल के पानी की गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित करनी होगी। पारदर्शी जल परीक्षण, परिणामों की सार्वजनिक उपलब्धता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था नागरिकों का भरोसा बहाल कर सकती है। साथ ही, जल अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी—चाहे वह पाइपलाइन की मरम्मत हो, सीवेज प्रबंधन हो या जल शोधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण।

इसके साथ-साथ जन जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझना होगा कि बोतलबंद पानी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों के बारे में जानकारी बढ़ाकर उपभोक्ता व्यवहार को बदला जा सकता है। स्कूलों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय निकायों की भूमिका इसमें अहम हो सकती है।

अंततः, बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता एक चेतावनी है। यह बताती है कि यदि सार्वजनिक जल प्रशासन को मजबूत नहीं किया गया, तो पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता भी गहरी असमानता और संकट का कारण बन सकती है। यह समय है कि राज्य, समाज और नागरिक मिलकर इस प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करें और पानी को फिर से भरोसे, समानता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के दायरे में वापस लाएं। केवल तभी भारत अपनी बढ़ती प्यास को न्यायपूर्ण और टिकाऊ तरीके से बुझा सकेगा।

संपादकीय

आफत से राहत

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला सीबीआई की तरफ से दायर मामले में आया है। अदालत ने सीबीआई की जांच में खामियों को उजागर करते हुए कहा कि आरोप गवाह या ठोस सबूतों पर आधारित नहीं हैं। अदालत का तर्क था कि चार्जशीट में उल्लेखित दावे तार्किक आधार नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति साल 2021 में लागू की थी। जिसके अंतर्गत शराब कारोबार निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन सरकार ने दलील दी थी कि नई नीति राज्य के राजस्व में आशातीत वृद्धि करेगी। बहरहाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल नैतिक रूप से खुद को बेहतर स्थिति में होने का दावा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल तथा 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। निश्चय ही संकट से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिये यह फैसला प्राणवायु जैसा साबित हो सकता है। दरअसल, कोर्ट ने इस बाबत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी का मामला न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। कोर्ट का कहना था कि अटकलों व अनुमानों को कानूनी रूप से मान्य सबूतों के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल व उनकी टीम के लिये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जिससे वे खुद को आम आदमी पार्टी के कोर वोटरों को अपने पाक-साफ होने का विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस प्रकरण को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखे हमले बोले थे। पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को यह समझाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी कि केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच है। बहरहाल, इन आरोपों के बीच स्वच्छ शासन का वादा करते हुए भाजपा ने 26 वर्ष के लंबे अंतराल पर दिल्ली की सत्ता में वापसी की थी, जबकि आप दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली विधानसभा में मिली शिकस्त के बाद ही आप के शीर्ष नेतृत्व ने अपना पूरा ध्यान पंजाब पर लगाया था। आज पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। भले ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है,लेकिन एक बात तो तय है कि निचली अदालत के आदेश के बाद आप को दिल्ली में खोये जनाधार को फिर से हासिल करने का मौका मिल सकेगा। वह अपनी पार्टी के मुख्य भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फिर से चलाने के लिये नैतिक बल तो हासिल कर पायी है। दरअसल, इस फैसले से जांच में अत्यधिक दखलंदाजी को लेकर कई असहज करने वाले सवाल भी उठे हैं। खासकर अदालत की वह टिप्पणी, जिसमें कहा गया कि जांच एक पूर्वनिर्धारित दिशा में चलती प्रतीत होती है। यानी जांच में उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा है कि आबकारी नीति मामले में जुड़ी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्र जांच मजबूत आधार रखती है। कानून के पंडित कयास लगा रहे हैं कि यदि सीबीआई मामले में निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा जाता है तो ईडी द्वारा अभियोजन की कानूनी वैधता पर नये सिरे से सवाल उठ सकते हैं।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की चर्चाः सत्य का आईना या संस्था की गरिमा पर प्रहार?

(लेखक - डॉ. प्रियंका सौरभ)

न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र का संरक्षक स्तंभ है, जो संविधान की रक्षा करता है और नागरिकों को न्याय का आश्वासन देता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की सोशल साइंस किताब पर सख्त रुख अपनाते हुए छपाई, वितरण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किताब के हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका अध्याय में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, लंबित मामलों की भारी संख्या, जजों की कमी और पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई के बयानों का उल्लेख था। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची-समझी साजिश करार दिया तथा शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। विवादित अध्याय के लेखकों की पहचान, उनकी योग्यता और सिलेबस फ्रेमिंग बैठकों की कार्यवाही प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह घटना न केवल शिक्षा नीति पर सवाल उठाती है, बल्कि संस्थागत गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के बीच संतुलन की बहस को जन्म देती है। क्या स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी चर्चा गलत है? या यह समाज को सतर्क करने का माध्यम है?

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(एक) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(दो) में उचित प्रतिबंध भी हैं, जिनमें न्यायालय की अवमानना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का कदम अवमानना अधिनियम 1971 के दायरे में आता है, जहां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री दंडनीय है। कोर्ट ने तर्क दिया कि अध्याय चुनिंदीय (सेलेक्टिव) था—न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का उल्लेख तो प्रमुख था, लेकिन विधायिका या कार्यपालिका पर ऐसा कोई जिक्र नहीं। लंबित मामलों को मैसिव बैकलॉग कहना और जजों की कमी को चुनौती के रूप में पेश करना संस्था को कमजोर दिखाता है। पूर्व सीजेआई गवई के बयान का संदर्भ बिना पूर्ण संदर्भ के लिया गया, जो भ्रामक था। कोर्ट ने इसे डीप-रूटेड कांस्पिरेसी कहा, जो संकेत देता है कि यह केवल शैक्षणिक चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रयास हो सकता है। एनसीईआरटी द्वारा हाल में संशोधित पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल करना शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही दर्शाता है। सिलेबस एक्सपर्ट कमिटी की बैठकों में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठे हैं—क्या लेखक राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित थे? कोर्ट ने गहन जांच का भरोसा दिलाया है, जो स्वागतयोग्य है।

भ्रष्टाचार पर चर्चा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 40/100 रहा, जो न्यायपालिका सहित संस्थाओं की चुनौतियों को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ब्रह्मावर्त हॉस्टल मामले या मेडिकल एडमिशन घोटालों में भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणियां की हैं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार का एक मामला भी पूरी संस्था को दागदार बनाता है। लेकिन स्कूली किताब में इसे सामान्यीकृत कर पेश करना उचित नहीं। बच्चे 13-14 वर्ष के होते हैं—उन्हें तथ्यपरक ज्ञान दें, न कि पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण। अध्याय जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण और सुधारों (जैसे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, जजों की भर्ती) पर केंद्रित होता तो उपयोगी होता। वर्तमान रूप में यह नकारात्मकता बोता है, जो युवा पीढ़ी में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां पंचायती राज मजबूत है, स्थानीय न्याय व्यवस्था पहले से जूझ रही है—ऐसी सामग्री से ग्रामीण बच्चे हतोत्साहित होंगे।

एनसीईआरटी की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम सरलीकृत और भारतीयता-केंद्रित बनाने का लक्ष्य था, लेकिन यह विवाद उलटा असर डाल रहा है। मंत्रालय को सिलेबस फ्रेमिंग में बहुपक्षीय परामर्श अनिवार्य करना चाहिए—शिक्षाविद्, न्यायिक विशेषज्ञ, अभिभावक संगठन शामिल हों। लेखकों की योग्यता जांचे—क्या वे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं या सामान्य शिक्षक? कोर्ट ने डिजिटल कॉपियां भी जब्त करने को कहा, जो साइबर युग में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह कदम आवश्यक था, क्योंकि गलत सूचना वायरल हो सकती थी। वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठों ने कोर्ट में इसे चुनिंदीय बताया, जो बहस को मजबूत करता है। अब जांच से यदि साजिश सिद्ध हुई, तो जिम्मेदारों पर अवमानना का मुकदमा चलेगा।

यह मामला व्यापक सुधारों की मांग करता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेएसी) को मजबूत बनाएं, जो जजों की नियुक्ति पारदर्शी करे। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को तेज करें, ताकि लंबित मामले घटें—वर्तमान 5 करोड़ से अधिक हैं। जजों की संख्या बढ़ाने हेतु विधायी सहमति लें। शिक्षा में भ्रष्टाचार को नैतिकता के अध्याय में शामिल करें, न कि संस्था-विशेष पर प्रहार के रूप में। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन संस्था की गरिमा सर्वोपरि। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सही दिशा में है—यह चेतावनी है कि शिक्षा भ्रष्टाचार नहीं बोएगी।एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम पुनरीक्षण कर तथ्यपरक, संतुलित सामग्री सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारें पारदर्शिता बढ़ाएं—आरटीआई से सिलेबस प्रक्रिया खुली हो। जनता जागरूक बने, क्योंकि मजबूत न्यायपालिका ही मजबूत भारत है। यदि भ्रष्टाचार पर चर्चा सुधार लाए, तो स्वागतयोग्य; अन्यथा यह साजिश मात्र। सुप्रीम कोर्ट की जांच से सत्य सामने आएगा, और शिक्षा प्रणाली मजबूत बनेगी। लोकतंत्र में संतुलन ही सफलता की कुंजी है।

ईश्वर हमेशा भक्तों की सहायता करता है

ईश्वर को हम भले ही न देख पाएं लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा होता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों एवं सद्व्यक्तियों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। शास्त्रों कहता है कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी संतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाये नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। गजराज की कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गये। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। सूरदास जी के जीवन की भी एक ऐसी ही कथा है। सूरदास जी देख नहीं सकते थे। एक बार गलती से एक गड्ढे में गिर गये। गड्ढे से निकलने का काफी प्रयास करने पर भी वह बाहर निकलने में असफल रहे। इस स्थिति में सूरदास जी ने गोपाल को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में पहुंच गये और सूरदास जी को गड्ढे से बाहर निकाला। मीरा के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने मीरा को मारने के लिए भेजे गये विष को प्रभावहीन कर दिया। बघेलखण्ड के बान्धवगढ़ में रहने वाले सेन नामक नाई की भी भगवान ने सहायता की और बघेलखंड का राजा सेन नाई का भक्त बन गया। यह घटना पांच छ सौ साल पुरानी है। सेन नाई राजा की सेवा करता था। इसका काम प्रतिदिन राजा की हजामत बनाना और तेल मालिश करके स्नान कराना था। एक दिन सेन नाई जब राजमहल की ओर चला तब रास्ते में संतों की टोली मिल गयी। नाई उन्हें लेकर घर आ गया और उनकी खूब सेवा की। संतों के साथ बैठकर सत्संग में भाग लिया।

राजा के स्नान करने का समय बीता जा रहा था। नाई के नहीं आने से राजा क्रोधित हो रहे थे। इसी समय भगवान स्वयं सेन नाई का वेष धारणकर राजा की सेवा में पहुंच गये। नई बने भगवान की सेवा से राजा का क्रोध दूर हो गया और मन हर्षित हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद सेन नाई को याद आया कि राजा की सेवा में देरी हो गयी है। हजामत का सामान लेकर डरता हुआ सेन नाई राजमहल में पहुंचा। राजा को देर से आने का कारण बताने लगा। इस पर राजा ने कहा कि तुम तो मेरी हजामत बना चुके हो। आज तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नाई समझ गया कि आज उसके कारण भगवान को नाई बनना पड़ा। इससे नाई को बड़ा अफसोस हुआ। राजा को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि नाई की भक्ति की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं आज नाई बनकर आये थे। राजा नाई की भक्त बन गया और उसे अपना गुरू मान लिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो ईश्वर के अस्तित्व और उसकी सहायता का प्रमाण देते हैं। इसलिए कभी भी खुद को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर आस्था रखने वालों की ईश्वर सदैव सहायता करते हैं।

विचार मंथन

दम है, तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाएं, मोदी

(लेखक - सनत जैन)

सीबीआई के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज का निर्णय दिया है। निर्णय में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में आबकारी नीति घोटाले के मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, बिना सबूत के आरोपियों को आपराधिक मुकदमे में घसीटना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आपराधिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल जांच एजेंसी द्वारा किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, न्यायिक जांच की कसौटी पर अभियोजन पक्ष जरा भी नहीं टिक पाया। कोर्ट ने आरोपियों को फंसाने के लिए व्यापक साजिश के दावे की पुष्टि की है। जो सीबीआई के लिए सबसे बड़ा झटका है। अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को पूर्व नियोजित और कोरियोग्राफड बताते हुए गंभीर टिप्पणी की है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा, आपराधिक मुकदमे में इस तरह से किसी को भी नहीं उलझा सकते हैं। राजनीतिक असहमति को आपराधिक मामलों के रूप में प्रस्तुत करने की कोर्ट ने तीव्र आलोचना फैसले में की है। उल्लेखनीय है, जांच एजेंसी ने साउथ लावी के नाम से तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी कविता को 165 दिन तक हिरासत में रखा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अकारण 181 दिनों तक जेल में बंद करके रखा गया था। इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने फैसले में उत्तर और दक्षिण के बीच में राजनीतिक विद्वेष फैलाने का कृत्य माना है। न्यायालय ने आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह को आरोपी नंबर एक बनाने पर कड़ी आपत्ति फैसले में दर्ज की है। सीबीआई ने जिस तरह से आबकारी नीति को जबरिया अपराध साबित करने के लिए एक के बाद एक कई लोगों को फंसाती चली गई। संदिग्ध गवाह बनाए गए। काल्पनिक सबूत बयान के आधार पर तैयार करने की कोशिश की गई। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई के अधिकारियों ने जांच करते हुए चुनाव प्रचार, होटल बुकिंग, और भुगतान इत्यादि की जांच की। चुनाव आयोग के अधिकारों का उपयोग सीबीआई ने किया है। अधिकारियों ने संविधानिक सीमाओं को पार किया है। जिन लोगों ने पैसे लेने और देने के आरोप स्वीकार किए थे। सीबीआई ने उन्हें गवाह बना लिया। उन गवाहों के बयान पर अन्य लोगों को फंसाया गया। अदालत ने फैसले में कहा अभियोजन के बयान की कॉपी अदालत को नहीं मिली। रिकॉर्ड को देखने से पता लगता है, जांच एजेंसी ने अदालत को भी दृग भ्रमित किया है। ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से सारे मामलों का विवेचन करते हुए सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, उसके बाद केंद्र सरकार, जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी द्वारा चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को प्रभावित किया गया है। इस सभी कार्यवाही का लाभ भाजपा को मिला। उसको लेकर देश में एक नया दबाव सत्ता पक्ष और जांच एजेंसियों के ऊपर पडना शुरू हो गया है। कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सियासी षड्यंत्र था। उनकी पार्टी के पांच बड़े नेताओं को चुनाव के पहले जेल में बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज कर आम आदमी पार्टी को बदनाम कर चुनाव लड़ने से रोकने का हर संभव प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में मोदी और शाह को चुनौती देते हुए कहा, यदि भाजपा में दम है, तो दिल्ली विधानसभा और लोकसभा का दोबारा चुनाव कराएं।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी और सभी विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। सीबीआई और ईडी द्वारा जिस तरह से विपक्षी राजनेताओं को निशाने पर लिया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं को आपराधिक मामले में फंसाया गया है। चुनाव के ठीक पहले दोनों एजेंसियां सीबीआई, ईडी और बाद में इसमें इनकम टैक्स भी शामिल हो गया था। पूरी तरह से सरकार के दबाव में विपक्षियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे। इस फैसले के बाद अब विपक्ष को नई संजीवनी मिल गई है। सत्ता पक्ष के लिए भविष्य में कानून और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना आसान नहीं होगा। अभी तक विपक्षी दल दबाव में थे। अब विपक्ष पूरी तरह से मुखर हो चुका है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जो विशेष अधिकार मिले थे, पिछले कई वर्षों से उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सत्ता पक्ष के लिए हो रहा था। जांच एजेंसी के पास विशेष अधिकार होने के कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विपक्षी नेताओं को ना तो राहत दे पा रहे थे, ना ही विपक्षी नेताओं के मामलों की सही सुनवाई हो पा रही थी। कोर्ट के अंदर ईडी के अधिकारी और वकील जो बोल देते थे, अदालतों को वही सच मानना पड़ता था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने इस फैसले में जिस तरह से सीबीआई जांच एजेंसी और उसके अधिकारियों की अवैधानिक कार्यवाही का उल्लेख किया है, उसके कारण जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार की मुसीबतें बढ़ना तय हो गई हैं। जांच एजेंसियों ने जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया होली ऑफर्स का ऐलान; शॉपिंग और ट्रैवल पर मिलेगी भारी छूट

क्रेडिट और डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए फेस्टिव सीजन में बचत का अवसर; 31 मार्च तक वैध रहेंगे ऑफर्स

मुंबई/इंदौर । भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू एसएफबी ने रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य में अपने ग्राहकों के लिए विशेष फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है। बैंक ने ग्रोसरी, फैशन शॉपिंग और ट्रैवल जैसी प्रमुख श्रेणियों में कैशबैक और डिस्काउंट के माध्यम से बचत के अवसर प्रदान किए हैं। यह पहल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर की गई है जो त्योहार के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदारी और यात्रा की योजना बना रहे हैं। बैंक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ग्रोसरी श्रेणी में स्विगी इंस्टामार्ट पर 111 रू. तक की छूट और ब्लिंकिट, जेप्टो व जियोमार्ट पर एयू क्रेडिट कार्ड के जरिए 5त्न की बचत की जा सकती है। फैशन शॉपिंग के लिए एजीओ (AJIO) पर 10त्न की विशेष छूट उपलब्ध है। वहीं, घर जाने या पर्यटन की योजना बना रहे ग्राहकों को रेडबस और अभिबस पर एयू क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10त्न तक की राहत मिलेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, अपने इन ऑफर्स के जरिए ग्राहकों के त्योहारी खर्च को किफायती बनाना चाहता है। ये सभी विशेष लाभ लाइव हो चुके हैं और ग्राहक इनका फायदा 31 मार्च 2026 तक उठा सकते हैं। बैंक का उद्देश्य उत्सव के इस माहौल में अपने कार्ड धारकों को वित्तीय लचीलापन और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

विशाल मेगा मार्ट की प्रवर्तक इकाई ने 13.96 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली । समायत सर्विसेज एलएलपी ने खुले बाजार में दो किस्तों में 65.25 करोड़ शेयर बेचे, जो कंपनी की कुल 13.96 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयरों का मूल्य 117-117.03 रुपए प्रति शेयर रहा, जिससे कुल लेनदेन मूल्य 7,635.55 करोड़ रुपए हुआ। इस बिक्री के बाद समायत सर्विसेज की विशाल मेगा मार्ट में हिस्सेदारी 54.09 फीसदी से घटकर 40.13 फीसदी रह गई। अभी भी यह सबसे बड़ा शेयरधारक है, लेकिन नियंत्रण पहले की तुलना में कम हुआ। समायत सर्विसेज एलएलपी एक विशेष-प्रयोजन इकाई है, जिसका स्वामित्व केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप, स्विट्जरलैंड के पास है। इस लेनदेन से निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं, और बाजार में स्थिर प्रतिक्रिया देखने को मिली।

सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण अस्थायी रूप से रोका

लंबे समय तक गोदाम में रखने पर आ रही पोषक तत्वों में कमी

नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) और अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्व मिलाने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार लंबे समय तक गोदामों में रखने से चावल में जो विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं, उनमें कमी आ रही थी। सरकार ने आईआईटी खड़गपुर को यह अध्ययन करने का काम सौंपा था कि अलग-अलग मौसम और वातावरण में चावल कितने समय तक सुरक्षित रहता है। रिपोर्ट में पाया गया कि चावल रखने का स्थान, तापमान, हवा में नमी और पैकिंग सामग्री फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर बड़ा असर डालते हैं। लंबे समय तक भंडारण और बार-बार परिवहन से पोषक तत्व जल्दी घट जाते हैं और चावल जल्दी खराब होने लगता है। राशन का चावल अक्सर 2-3 साल तक सरकारी गोदामों में रखा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए सालाना 372 लाख टन चावल की जरूरत होती है। जबकि सरकारी भंडार में कुल उपलब्धता लगभग 674 लाख टन है, जिसमें 2025-26 की खरीफ फसल भी शामिल है। खाद्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पोषक तत्व मिलाने की प्रक्रिया रोकने से राशन की मात्रा या स्कूलों और आंगनवाड़ी में मिलने वाले मध्याह्न भोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पीपीएफ में एक व्य क्ति अपने नाम पर खोल सकता है केवल एक खाता

- संयुक्त खाते की अनुमति भी नहीं

नई दिल्ली ।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) भारत में सबसे भरोसेमंद बचत योजनाओं में से एक है। वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। यह खाता बैंक में हो या डाकघर में, फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त खाते की अनुमति भी नहीं है। अगर किसी के नाम पर एक से अधिक खाते पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त खाते को अनियमित माना जा सकता है और उसमें जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकती है। पीपीएफ खाते व्यक्ति के पैन नंबर से लिंक होते हैं। इसलिए अलग-अलग बैंक या डाकघर में खाते खोलकर अधिक टैक्स फायदा लेने की कोशिश सिस्टम में पकड़ी जा सकती है। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए पीपीएफ खाता खोल सकता है। लेकिन नियम स्पष्ट करते हैं कि एक बच्चे पर सिर्फ एक खाता ही खोला जा सकता है और दूसरे अभिभावक को उसी बच्चे के नाम पर खाता खोलने की अनुमति नहीं है। पीपीएफ में न्यूनतम जमा 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष है। यह सीमा कुल मिलाकर लागू होती है, यानी अभिभावक अपने खाते और नाबालिग बच्चों के खातों में मिलाकर भी 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकता। नाबालिग खाते खोलने से कुल टैक्स लाभ की सीमा बढ़ती नहीं है। पीएफ योजना लंबी अवधि के लिए डिज़ाइन की गई है। एक से अधिक खाते खोलकर अधिक टैक्स लाभ लेने की कोशिश नियमों के खिलाफ है। अगर निवेशक 1.5 लाख रुपये से अधिक बचत करना चाहता है, तो उसे अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना होगा।

टाटा संस में चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर फैसला टला

- प्रस्ताव को लेकर समूह में मतभेद की अटकलें बढ़ीं

नई दिल्ली । टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर निदेशक मंडल ने फैसला टाल दिया। यह बैठक ऐसे समय हुई जब टाटा ट्रस्ट, जो टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, ने पिछले साल सर्वसम्मति से उन्हें तीसरा कार्यकाल देने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति को लेकर कुछ शर्तें रखी थीं, जो इस प्रकार हैं- एयर इंडिया का अधिग्रहण और कंपनी के घाटे को लेकर चिंता, सेमीकंडक्टर और बैटरी उत्पादन जैसे नए क्षेत्रों में भारी पूंजीगत जोखिम, नियामकीय बाध्यता और टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने संबंधी स्पष्ट आश्वासन की मांग। इन शर्तों और चिंताओं के कारण बोर्ड ने निर्णय को स्थगित कर दिया। टाटा ट्रस्ट का सर्वसम्मत प्रस्ताव अभी भी कायम है लेकिन पर्यवेक्षकों ने सवाल उठाया कि क्या ट्रस्ट के नामित निदेशक निदेशक मंडल में अलग रुख अपना सकते हैं। यह स्थिति समूह के उच्चस्तरीय मतभेद और रणनीतिक चिंताओं का संकेत देती है।

सोने की बढ़ती कीमतों से गोल्ड लोन बाजार में रिकॉर्ड उछाल

- जनवरी में गोल्ड लोन में 128 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई

नईदिल्ली ।

सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सीधा असर बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रहा है। जनवरी में गोल्ड लोन में 128 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले साल जनवरी (91 फीसदी) से काफी अधिक है। रिजर्व बैंक आफ इं डिया (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, गोल्ड जूलरी के बदले बैंकों का आउटस्टैंडिंग लोन पहली बार 4,00,517 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। सोने की कीमतों में 152 फीसदी की बढ़ोतरी ने इस लोन की मांग को मजबूत आधार दिया है। बैंक क्रेडिट में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 9 फीसदी रही। जनवरी में कुल बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14.4 फीसदी रही। पर्सनल लोन बैंक क्रेडिट का सबसे बड़ा सेगमेंट बना, जिसमें हिस्सेदारी 34.5 फीसदी रही। रिटेल लोन में 15 फीसदी की तेजी आई, जबकि एजुकेशन लोन दूसरे सबसे तेज बढ़ने वाले सेगमेंट के रूप में सामने आया, जिसमें 14 फीसदी वृद्धि हुई। सेक्टरवार आंकड़ों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 62 फीसदी की उछाल दर्ज हुई, जिसे आरबीआई ने अनिवार्य कर्ज श्रेणी में शामिल किया है। इसके अलावा, जेम्स एंड जूलरी तथा इंजीनियरिंग सेक्टर में 36 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जो इन्हें सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल करता है। कॉरपोरेट सेक्टर में कर्ज वृद्धि 12 फीसदी रही, जबकि नॉन-फूड क्रेडिट 14 फीसदी बढ़ा। अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के कारण जनवरी में एक्सपोर्ट क्रेडिट 17.2 फीसदी घट गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई थी। यह वैश्विक आर्थिक बदलाव का असर भारतीय क्रेडिट मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है।

भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह मिलाजुला रुझान देखा गया

सेंसेक्स और निफ्टी में साप्ता हिक आधार पर एक फीसदी से अ धिक तेजी रही

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह मिश्रित रुझान दिखाया, जिसमें शुरुआती मजबूती के बाद मध्य और अंत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजार के कमजोर संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच भारतीय बाजारों में स्थिरता बनी रही, निवेशकों का नजरिया तेजी से सतर्क हो गया। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष ने भी बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस तनाव की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। जिससे सप्ताह के ओ खिर में शेयर बाजार में एक फीसदी से अे धिक की गिरावट देखी गई। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को हरे निशान से हुई, जब वैश्विक बाजारों में तेजी और बैंक एवं सेवा क्षेत्र में खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स ने 621.78 अंकों की बढ़त के साथ 83,436.49 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 180.05 अंकों की तेजी के साथ 25,751.30 पर कारोबार शुरू किया। दिन के अंत तक सेंसेक्स 479.95 अंक और निफ्टी 141.75 अंक ऊपर बंद हुए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वैश्विक व्यापार की धाराओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा। मंगलवार को बाजार में अचानक गिरावट देखने को मिली। एआई से जुड़े संभावित व्यवधानों और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स 525.29 अंक गिरकर 82,769.37 पर और निफ्टी 145.85 अंक घटकर 25,567.15 पर खुला। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,068.74 अंक और निफ्टी 288.35 अंक गिरकर सप्ताह के शुरुआती उत्साह को झटका लगा। बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बढ़त देखी गई, लेकिन दिन के अंत में सूचकांक केवल मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। गुरुवार को आईटी शेयरों में खरीदारी और विदेशी फंड प्रवाह ने शुरुआती कारोबार में बाजार को बढ़त दिलाई। हालांकि, दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 27.46 अंक गिरकर और निफ्टी 14.05 अंक बढ़कर सपाट बंद हुए। शुक्रवार को वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी फंडों की नई निकासी के

चलते दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही। सेंसेक्स 961.42 अंक गिरकर 81,287.19 पर और निफ्टी 317.90 अंक घटकर 25,178.65 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह अत्यधिक अस्थिरता दिखाई। शुरुआती उत्साह के बाद मध्य सप्ताह में आईटी शेयरों और वैश्विक जोखिमों के कारण गिरावट देखी गई, जबकि सप्ताह के अंत में विदेशी फंड निकासी और वैश्विक दबाव ने बाजार को लाल निशान में बंद करवाया। निवेशकों के लिए यह सप्ताह सीखने और सतर्क रहने का रहा।

अमेरिका और ईरान में जंग.....सोना 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 300000 लाख रुपये

मुंबई ।

इजरायल ने फिर ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षामंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले पर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान की प्रतिक्रिया जिस तरह से सामने आई है उससे साफ है कि यह तनाव शायद ही जल्द समाप्त हो। अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तब इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर होगा। आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के दाम इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि घरेलू बाजार में सोने का भाव 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी फिर से 300000 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं, ÷अमेरिका-ईरान तनाव की वजह से अनिश्चितता के दौर में इजाफा होगा। निवेशक ऐसी परस्थिति में सुरक्षित निवेश की तलाश करेगा। हम सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं, ÷सीओएमईएक्स गोल्ड रेट 5300 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके ऊपर जाने पर भारत में सोने का भाव 168000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 170000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है।÷

शुक्रवार को सीओएमईएक्स सिल्वर रेट 93 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें 95 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एक्सपर्ट मानते हैं, ÷अगर सीओएमईएक्स सिल्वर रेट 95 डॉलर प्रति आउंस के स्तर को क्रॉस करने

में सफल रही तब यह फिर से 100 डॉलर प्रति आउंस के स्तर तक पहुंच सकती है। भारत में चांदी की कीमतें फिर से 300000 लाख रुपये के स्तर तक जा सकता है।÷ हालिया समय में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिली है। हालांकि, उस हिसाब से फरवरी का महीना नहीं बीता है।

गोल्ड और सिल्वर एटीएफ का एनएवी अब भारतीय बाजार की कीमत पर

-अब ईटीएफ का एनएवी ज्यादा पारदर्शी और भारतीय बाजार के अनुकूल होगा

नई दिल्ली । अभी तक गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ अपने पास रखे सोने और चांदी की कीमत तय करने के लिए एलबीएमए (लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन) की एएम फिक्सिंग का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद कई चरणों में बदलाव किया जाता था, जैसे डॉलर से रुपये में बदलना, आयात शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ढुलाई खर्च और अन्य टैक्स या फीस। इस वजह से निवेशकों के लिए ईटीएफ का एनएवी वास्तविक भारतीय बाजार की कीमत से थोड़ा अलग दिखाई देता था। 1 अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया बदल जाएगी। अब ईटीएफ ,को अपने बुलियन होल्डिंग की कीमत तय करने के लिए भारतीय एक्सचेंजों द्वारा जारी डॉमेस्टिक स्पॉट प्राइस का उपयोग करना होगा। ये वही कीमतें हैं जिन पर एमसीएक्स और एनएसई पर फिजिकल सोना-चांदी के सौदे होते हैं। इसका मतलब एनएवी सीधे भारत के बाजार की वास्तविक कीमत को दिखाएगा। इस बदलाव से ईटीएफ का एनएवी ज्यादा पारदर्शी और भारतीय बाजार के अनुकूल होगा। डॉलर-रुपये के बदलाव या अतिरिक्त शुल्क जोड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। निवेशकों के लिए सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रोज़ाना की कीमतें अब भारत के फिजिकल मार्केट के हिसाब से तय होंगी।

भारत, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते में मध्यस्थता से जुड़ा परिशिष्ट शामिल

- समझौते पर विधिक परीक्षण के बाद हस्ताक्षर होने की संभावना

नई दिल्ली।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के निष्कर्ष की घोषणा की। समझौते पर विधिक परीक्षण के बाद हस्ताक्षर होने की संभावना है और इसे अगले वर्ष लागू किया जा सकता है। एफटीए में मॉडल मध्यस्थता प्रक्रिया पर एक अलग परिशिष्ट शामिल है, जिसका उद्देश्य विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान करना है। समझौते के अनुसार भारत या ईयू कोई भी पक्ष ऐसे उपाय के खिलाफ मध्यस्थता की मांग कर सकता है, जो द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

हालांकि प्रक्रिया केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही शुरू होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बनती, तो मध्यस्थता का अनुरोध स्वतः निरस्त माना जाएगा। मध्यस्थता आम तौर पर उस पक्ष के क्षेत्र में होगी, जिसके पास अनुरोध भेजा गया है, या आपसी सहमति से किसी अन्य स्थान या माध्यम से भी इसे आयोजित किया जा सकता है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। करीब दो दशक चली वार्ताओं के बाद संपन्न एफटीए के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि ईयू से लक्जरी कार और वाइन का आयात सस्ता होगा। दोनों पक्ष वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा नियंत्रित करते हैं।

समझौते में कुल 20 अध्याय शामिल हैं, जिनमें डिजिटल व्यापार पर अलग अध्याय भी है। यह कागज-रहित व्यापार, नियामकीय सहयोग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा विवाद निपटान पर अलग अध्याय विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान की व्यवस्था करता है।

फरवरी में सीमेंट की औसत कीमत 342 रुपये प्रति बोरी पहुंची

- कुछ राज्यों में मार्च में फिर बढ़ोतरी की तैयारी

नई दिल्ली ।

फरवरी में सीमेंट बाजार ने मिलीजुली तस्वीर पेश की। जनवरी में बढ़ी कीमतों के बाद उम्मीद थी कि रुझान और मजबूत होगा, लेकिन स्थिति न तो बहुत तेज रही और न ही पूरी तरह सुस्त। पूरे देश में औसत ट्रेड कीमत 2 रुपये बढ़कर 342 रुपये प्रति बोरी हो गई। क्षेत्रीय तौर पर हालात अलग रहे। पश्चिम भारत में दाम 7 रुपये प्रति बोरी तक बढ़कर सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। पूर्व में 4 रुपये और उत्तर में 3 रुपये की तेजी रही। मध्य भारत में कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि दक्षिण भारत में औसतन 2 रुपये प्रति बोरी की गिरावट दर्ज की गई। कुछ बाजारों में महीने की शुरुआत में बढ़ी कीमतें बाद में सामान्य हो गईं। जनवरी और फरवरी मिलाकर चालू तिमाही में औसत दाम पिछली तिमाही से करीब 1 प्रतिशत अधिक रहे। इससे कंपनियों को थोड़ी राहत मिली। बाजार को इस बार बड़े निर्माण और सरकारी प्रोजेक्ट्स का सहारा मिला। खुदरा बाजार में दाम 0 से 15 रुपये प्रति बोरी ऊपर-नीचे रहे, जबकि बड़े ऑर्डर वाले सौदों में 0 से 20 रुपये तक बढ़त दर्ज हुई। ज्यादातर जगहों पर मांग जनवरी की तुलना में बेहतर रही, लेकिन खुदरा खरीदार अभी पूरी ताकत से नहीं उतरे। मार्च के पहले 10 दिन होली के कारण कामकाज धीमा रह सकता है। मार्च में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना ज्यादातर इलाकों में कम है। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 10-15 रुपये प्रति बोरी तक दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मांग ठीक है, इसलिए अचानक बड़ी गिरावट की संभावना कम है। असली परीक्षा यह होगी कि कंपनियां बढ़े हुए दाम को कितने समय तक संभाल पाती हैं।

क्रेडिट कार्ड नियमों में संभावित बदलाव 1 अप्रैल से

क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार

नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। खरीदारी, यात्रा, ऑनलाइन बिल और टैक्स भुगतान में उनका उपयोग तेजी से बढ़ा है। 1 अप्रैल से इन कार्डों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जो सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे। नए नियमों के तहत सालभर में किए गए बड़े भुगतान पर विशेष नजर रखी जा सकती है। यदि कोई निर्धारित सीमा से अधिक क्रेडिट कार्ड बिल जमा करता है, तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी जा सकती है। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और अनियमित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। डिजिटल और नकद भुगतान के लिए अलग-अलग सीमा तय की जा सकती है। तय सीमा से अधिक नकद जमा करने पर इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है। इससे बड़ी रकम को बिना रिकॉर्ड के चुकाना मुश्किल होगा और नकद भुगतान करने वालों को पहले से योजना बनानी होगी। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है। यह नए कार्ड आवेदन या अपडेट के समय लोगों को अतिरिक्त विकल्प देगा, खासकर उनके लिए जिनके पास सीमित दस्तावेज हैं। सरकार कार्ड को टैक्स और जीएसटी भुगतान के लिए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है। कंपनियों द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट कार्ड पर भी खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना और निजी व ऑफिस खर्च अलग दिखाना अनिवार्य हो सकता है। नए कार्ड के लिए पैन नंबर अनिवार्य हो सकता है। कार्डधारकों को बड़े लेन-देन की सीमा, नकद भुगतान नियम, प्रोसेसिंग फीस और खर्च का रिकॉर्ड ध्यान से रखना चाहिए।

तेल की कीमतें भू-राजनीतिक तनाव में मारती हैं उछाल

नई दिल्ली ।

पिछले 50 वर्षों में बड़े युद्ध और भू-राजनीतिक संकट अक्सर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल लाते रहे हैं। 1970 के दशक में अरब देशों द्वारा निर्यात रोकने से तेल 3 से 12 डॉलर तक बढ़ा। 1990 में इराक-कुवैत युद्ध और 2003 में दूसरे इराक युद्ध में भी कीमतें 40 फीसदी तक बढ़ीं, लेकिन सप्लाई बढ़ने पर जल्द सामान्य हुईं। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान तेल 80 से डालर 120 प्रति बैरल तक गया, फिर वैकल्पिक खरीदारों के आने से छह महीनों में दाम सामान्य हुए। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान का उत्पादन वैश्विक तेल सप्लाई का केवल 3 फीसदी है, लेकिन इसका भू-राजनीतिक महत्व बड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते दुनिया की लगभग 20 फीसदी तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। इस मार्ग में कोई बाधा आने पर सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई की सप्लाई सीधे प्रभावित हो सकती है। हाल के तनाव के कारण कीमतों में लगभग 10 फीसदी की तेजी देखी गई। विश्लेषकों का कहना है कि हर 1 फीसदी सप्लाई झटके से तेल की कीमत 3-5 फीसदी बढ़ती है। अगर ईरान का 3.3 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन रुकता है, तो 70 डॉलर के

बेस प्राइस पर दाम 76-81 डॉलर तक जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर गंभीर खतरे के मामले में अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम 20-40 डॉलर जुड़ सकता है, जिससे कीमत 95-110 डॉलर या उससे ऊपर पहुंच सकती है। इतिहास और विशेषज्ञों की राय यही दर्शाती है कि तेल की कीमतें भू-राजनीतिक तनाव में तेजी दिखा सकती हैं, लेकिन वास्तविक सप्लाई बाधा अक्सर अस्थायी होती है। बाजार में भय और अनिश्चितता ही दामों को अस्थायी रूप से ऊंचा करती है, जबकि संतुलन बहाल होने पर कीमतें सामान्य स्तर पर लौट आती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत बनाम वेस्टइंडीज: सेमीफाइनल की राह तय करेगा कोलकाता का महामुकाबला, मौसम देगा पूरा साथ

कोलकाता (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे अहम मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच विजेता ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा। यह मैच किसी क्वार्टरफाइनल से कम नहीं माना जा रहा है क्योंकि दोनों टीमों के पास आगे बढ़ने का यही आखिरी मौका है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों की दमदार जीत के साथ अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब टीम इंडिया को शाई होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को हराना अनिवार्य है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज भी जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक बन गया है।

मुकाबला रविवार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स इस हाई-वोल्टेज मैच का गवाह बनने जा रहा है। फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल मौसम को लेकर है क्या बारिश मैच बिगाड़ सकती है? शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, राहत की खबर है कि 1 मार्च को कोलकाता में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है। दिन में तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक और शाम को 25-26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम क्रिकेट के लिए आदर्श माना जा रहा है और फैंस को पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है।

हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन यदि मैच किसी कारणवश रद्द होता है तो स्थिति दिलचस्प हो जाएगी। फिलहाल दोनों टीमों के पास 2-2 अंक हैं। मैच रद्द होने पर दोनों को एक-एक अंक मिलेगा और अंक तीन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बेहतर नेट रन रेट होने

के कारण वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है, जिससे भारत का सफर यहीं समाप्त हो सकता है। ऐसे में भारत को न सिर्फ जीत, बल्कि मौसम के पूरी तरह साथ देने की भी उम्मीद रहेगी। अब देखना है कि ईडन गार्डन्स में कौन सी टीम अपना 'करो या मरो' मुकाबला जीतकर अंतिम-चार में जगह बनाती है।

टीम इस प्रकार है

भारत: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज : ब्रैंडन किंग, शाइ होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोस्टन चेस, जॉनसन चार्ल्स।

आवासीय प्लॉट के कथित दुरुपयोग पर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस, हाउसिंग बोर्ड ने मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से रांची में आवासीय प्लॉट के कथित दुरुपयोग के मामले में नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। धोनी जहां एक ओर आईपीएल 2026 में खेलने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह विवाद उनके पुराने आवास से जुड़े उपयोग को लेकर चर्चा में है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार धोनी को जो प्लॉट आवंटित किया गया था, वह केवल आवासीय उपयोग के लिए था, लेकिन आरोप है कि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है। बोर्ड की ओर से भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं थी।

झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजयलाल पासवान ने बताया कि क्षेत्र में कई प्लॉट आवासीय उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि कुछ भूखंडों पर व्यवसायिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी आधार पर धोनी सहित कई अन्य लोगों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक यह अंतिम नोटिस है और यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्लॉट के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। धोनी फिलहाल रांची के रिंग रोड स्थित अपने नए आवास में रहते हैं। विवादित संपत्ति उनका पुराना घर है, जो हरमू रोड पर स्थित है। आरोप है कि इस संपत्ति में एक डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने जांच आरंभ की। इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय को भी आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग पर पहले नोटिस जारी किया जा चुका है। इधर, धोनी मैदान पर वापसी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके धोनी 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2026 में एक बार फिर खेलते नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति को लेकर प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

वानखेड़े में रवि शास्त्री के नाम पर स्टैंड, तीन दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर होंगे स्टेडियम के गेट

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने मुंबई और भारतीय क्रिकेट की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में लेवल-1 स्टैंड का नाम पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री के नाम पर रखा जाएगा। इसी के साथ स्टेडियम के तीन प्रमुख गेट भी शहर के कुछ महान खिलाड़ियों को समर्पित किए जाएंगे। यह फैसला एमसीए की हालिया एपेक्स काउंसिल बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

एमसीए ने बताया कि प्रेस बॉक्स के ठीक नीचे स्थित लेवल-1 स्टैंड अब रवि शास्त्री के नाम से जाना जाएगा। खिलाड़ी, कप्तान, कोच और कमेंटेटर के रूप में भारतीय क्रिकेट को उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में यह निर्णय लिया गया है। भारतीय क्रिकेट में चार दशक से अधिक समय तक उनकी भूमिका ने उन्हें खेल का एक बड़ा चेहरा बनाया है। स्टेडियम के गेट भी मुंबई क्रिकेट के तीन दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। गेट नंबर 3 का नाम महान बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने 30 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। गेट नंबर 5 महिला क्रिकेट की अग्रणी हस्तियों में शामिल डायना एडुल्जी को समर्पित होगा, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया। वहीं गेट नंबर 6 अब प्रसिद्ध ऑलराउंडर और क्लोज-इन फील्डर एकनाथ सोलकर के नाम से जाना जाएगा, जो अपनी फुर्ती और साहसिक फील्डिंग के लिए याद किए जाते हैं। एमसीए अध्यक्ष अजींक्य नाइक ने कहा कि मुंबई क्रिकेट की मजबूत आधारशिला इन खिलाड़ियों ने अपने खेल और अनुशासन से तैयार की है। उन्होंने कहा कि इन दिग्गजों का सम्मान करना न केवल अतीत की विरासत को सलाम करना है, बल्कि भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में प्रवेश करने वाले हर दर्शक को अब मुंबई क्रिकेट की गौरवशाली यात्रा और इन महान खिलाड़ियों के योगदान की याद ताजा होगी। एमसीए के इस फैसले को क्रिकेट जगत में सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर की क्रिकेट संस्कृति और खिलाड़ियों की विरासत को नए सिरे से

टी20 वर्ल्ड कप 2026: दक्षिण अफ्रीका की जीत की लय पर जिम्बाब्वे की चुनौती

-अरुण जेटली स्टेडियम में होगा हाई-स्टेक मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में रविवार दोपहर नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे आमने-सामने होंगी। प्रोटियाज अपनी अजेय लय को सात मैचों तक बढ़ाना चाहेंगे, जबकि जिम्बाब्वे टूर्नामेंट का समापन सम्मानजनक तरीके से करना चाहेगा। दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में अब तक अपने सभी छह मुकाबले जीत चुका है और 10 के नेट रन रेट के साथ सबसे दमदार टीम के रूप में उभरा है। टीम अगर जिम्बाब्वे को मात देती है, तो यह टी20 प्रारूप में उसकी दूसरी सबसे लंबी जीत की श्रृंखला बन जाएगी। कप्तान एडन मार्क्रम बेहतरीन फॉर्म में हैं। वे 178 की स्ट्राइक रेट से 264 रन बना चुके हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा है, जो 50 से ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे ऊंचा है। मार्कराम के पास बाबर आजम (303 रन, 2021) के रिकॉर्ड को तोड़कर एक वर्ल्ड कप संस्करण में कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का मौका भी है।

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी स्पिन के खिलाफ सबसे प्रभावी रही है, जहां टीम ने 9.9 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक को छोड़कर लगभग सभी बल्लेबाज 140+ के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में भी टीम का प्रदर्शन शानदार है। तेज गेंदबाज 37 विकेट चटका चुके हैं, जो इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक हैं। लुंगी एंगीडी 11 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। मार्को जानसेन के नाम भी 11 विकेट हैं, जबकि कगिसो रबाडा ने शुरुआती मैचों के बाद जोरदार वापसी की है।

जिम्बाब्वे की टीम भले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनके अभियान में कई यादगार पल शामिल रहे। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल किया था, हालांकि सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार से टीम की रफ्तार टूट गई। जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। वे अभी तक पांच पारियों में 277 रन बना चुके हैं और केवल एक बार आउट हुए हैं। उन्हें इस वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली (319 रन) के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल 43 रन की जरूरत है।

नई दिल्ली की पिच पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है। यहां खेले गए पांच में से चार मैच दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। हेड-टू-हेड मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका 7-1 से आगे है, जिससे वह इस मैच में स्पष्ट रूप से मजबूत दावेदार दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि दक्षिण अफ्रीका अपनी जीत की लय बरकरार रखता है या जिम्बाब्वे आखिरी मुकाबले में बड़ा उलटफेर करता है।

रणजी ट्रॉफी जीत के बाद भावुक हुए पारस डोगरा, बोले 'यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि'

हुबली। हुबली में इतिहास रचने के बाद पारस डोगरा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल ड्रॉ रहने के बावजूद पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दर्ज करने वाली जम्मू-कश्मीर के कप्तान ने कहा कि इस सफलता को शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल है। मैच के बाद डोगरा ने कहा, "सच कहूं तो मैं इसे समझा नहीं सकता। मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं हैं। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं।" उन्होंने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत सामूहिक मेहनत का नतीजा है। जम्मू-कश्मीर ने फाइनल में पहली पारी में 291 रन की भारी बढ़त लेकर मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली थी। कर्नाटक के लिए वापसी का एकमात्र रास्ता था कि दूसरी पारी में विरोधी टीम को जल्दी आउट किया जाए। शुरुआती झटकों के बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण लग रही थी, जब टीम 11/2 पर लड़खड़ा गई थी।

पिता के निधन के बाद टीम से जुड़ें रिंकू सिंह, देश के लिए निभाई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्टार रिंकू सिंह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इस गहरे दुख के बावजूद रिंकू ने हिम्मत दिखाते हुए टीम इंडिया में दोबारा शामिल हो गए है और वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के इडन गार्डन में होने वाले मैच के लिए तैयार हैं। रिंकू 26 फरवरी को भारत और जिम्बाबे के बीच खेले गए मैच में मैदान पर मौजूद थे। हालांकि वे प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सब्सटीट्यूट फील्डर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मैच खत्म होने के कुछ घंटे बाद, 27 फरवरी की सुबह उन्हें उनके पिता खानचंद सिंह के निधन की दुखद सूचना मिली। उनके पिता लिवर कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे। सूचना मिलते ही रिंकू चेन्नई से सीधे अपने शहर अलीगढ़ पहुँचे और अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। इससे पहले भी, वह टूर्नामेंट के दौरान अपने पिता की खराब तबीयत के चलते अस्पताल गए थे, लेकिन देश की जिम्मेदारी को देखते हुए टीम के साथ ज़िम्बाब्वे मैच से पहले फिर जुड़ गए थे। भारत का अगला और बेहद अहम मुकाबला 1 मार्च को इडन गार्डन में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच किसी क्वार्टर फ़ाइनल से कम नहीं है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। टीम की जरूरत को देखते हुए रिंकू का यह फैसला क्रिकेट जगत और प्रशंसकों के बीच बेहद सराहा जा रहा है। निजी त्रासदी के बावजूद देश के लिए तत्पर रहने का उनका यह साहसिक कदम युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।

तीसरे वनडे में साख बचाने उतरेगी भारतीय महिला टीम

-बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार की सख्त जरूरत

होबार्ट (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में एकतरफा हार झेलने के बाद मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर खड़ी है। रविवार को होबार्ट में होने वाला तीसरा और अंतिम महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारत के लिए केवल सम्मान बचाने का मौका है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त लेकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है और यह लगातार 12वीं बार है जब भारत द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में इस प्रतिद्वंद्वी से हार चुका है। भारत की सबसे बड़ी चिंता उसकी कमजोर बल्लेबाजी रही है। पहले वनडे में पावरप्ले के भीतर ही तीन महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद टीम 214 पर सिमट गई। दूसरे वनडे में हालांकि टीम ने 78 रनों की शानदार साझेदारी से शुरुआत की, लेकिन मध्य और निचले क्रम ने इसे भुनाया नहीं। 17वें से 31वें ओवर के बीच मात्र 52 रनों पर पांच विकेट गंवाना टीम के पतन की बड़ी वजह रहा। परिणामस्वरूप भारत नौ विकेट पर 251 रन ही बना पाया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया।

टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जहां

दो अर्धशतक जड़े, वहीं युवा सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल ने शून्य पर आउट होने के बाद शानदार अर्धशतक से वापसी की। स्मृति मंधाना भी दो मैचों में 31 और 58 रन बनाकर अच्छी लय में दिखीं। लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा का फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हरमनप्रीत ने भी स्वीकार किया कि टीम ने बार-बार वही गलतियां दोहराईं और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट गंवाए जिससे बड़ा स्कोर खड़ा नहीं हो सका। भारत की गेंदबाजी की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं दिखी। दीप्ति ने दो मैचों में तीन विकेट जरूर लिए, लेकिन उनके अलावा तेज गेंदबाज काशवी गौतम और क्रांति गौड़ को पावरप्ले में अधिक प्रभावी होने की जरूरत है। श्री चरणी पहले मैच में दो विकेट लेने के बाद दूसरे मैच में काफी महंगी साबित हुईं। खराब फील्डिंग ने टीम की परेशानियां और बढ़ाईं गौड़, मंधाना और ऋचा घोष के कैच छोड़ने से ऑस्ट्रेलिया को और बढ़त मिली।

इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हर विभाग में अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरे वनडे में जॉर्जिया वोल के दमदार शतक और फीबी लिचफील्ड की शानदार बल्लेबाजी ने मैच को एकतरफा बना दिया। पहले मैच में बेथ मूनी, एलिसा हीली और एनाबेल सदरलैंड ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी में मेगन शट, एशले गार्डनर, अलाना किंग और सदरलैंड ने लगातार विकेट निकालकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। भारत भले ही टी20 श्रृंखला 2-1 से जीत चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दो वनडे की जीत ने बहु-प्रारूप श्रृंखला में उसे 6-4 की बढ़त दिला दी है। भारत को न केवल तीसरे वनडे में बल्कि पर्थ में होने वाले एकमात्र टेस्ट में भी दम दिखाना होगा, ताकि इस दौरे का अंत निराशाजनक न हो और टीम अपनी प्रतिष्ठा बचा सके।

टीम इस प्रकार हैं

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, काशवी गौतम, हरलीन देयोल, प्रतिका रावल।

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनी (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फीबी लिट्चफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलीसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

'संजू सैमसन को अब मौका लपकना होगा' : अश्विन

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहली बार पूरी तरह चमककर सामने आई जब ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका था और सुपर-8 का पहला मुकाबला टीम हार चुकी थी। सेमीफाइनल की उम्मीदें 'अगर-मगर' पर टिकी थीं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने टूर्नामेंट में नई जान फूंक दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 256 रन खड़ा किया और मुकाबला 72 रन से जीत लिया। इस मैच में संजू सैमसन को मौका दिया गया और उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में उतारा गया। दोनों ने सिर्फ 22 गेंदों में 48 रन की तेज साझेदारी की। सैमसन 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने पावरप्ले में वह आक्रामक शुरुआत दे दी जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। इस दमदार जीत और सैमसन की पारी पर दिग्गज ऑफ स्पिनर रवचन्द्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर खास प्रतिक्रिया दी। अश्विन ने कहा कि सैमसन को आक्रामक क्रिकेट के रास्ते पर चलते रहना होगा और यह उनके लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा, 'मैं जिस संजू सैमसन को जानता हूं, मुझे उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। भारत को वर्ल्ड कप के दौरान ओपनिंग में समस्या थी, लेकिन इस मैच ने उसे दूर कर दिया। अगर सैमसन यहां से फाइनल तक 15 गेंदों में 28 या 30 रन भी बना देते हैं, तो वह टीम के लिए अपना काम कर चुके होंगे। बड़े स्कोर भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका यही है तेजी से टीम को शुरुआत देना।' अश्विन ने आगे कहा कि वे सैमसन को बड़ी पारी खेलते देखना चाहते हैं। 'मैं चाहता हूं कि सैमसन अच्छी शुरुआत को मैच-विनिंग पारी में बदलें। यह उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका है। सालों की मेहनत के बाद इस मंच तक पहुंचे हैं, उन्हें इसे पकड़ना होगा। अगर नाकाम भी होते हैं, तो यह जरूर कह पाएंगे कि उन्होंने कोशिश की। मैं चाहता हूं कि वह इस वर्ल्ड कप में एक शतक लगाएं या मैच जिता दें वे इसके हकदार हैं।' भारत के लिए अब अगला और सबसे अहम सुपर-8 मुकाबला 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। यह मैच क्वार्टर फाइनल जैसा है जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में जाएगी। ग्रुप-1 से दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। ऐसे में सैमसन और टीम इंडिया पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट का नया सूरज, रणजी ट्रॉफी जीतकर मनाया जश्न, पीएम मेदी ने दी बधाई

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर टीम को उनकी पहली रणजी ट्रॉफी जीत पर बधाई दी और उनके असाधारण साहस, अनुशासन और जुनून की सराहना की। जम्मू और कश्मीर ने 67 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शनिवार को हुबली में खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मजबूत टीम कर्नाटक को हराया। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि जम्मू और कश्मीर टीम को उनकी पहली रणजी ट्रॉफी जीत पर बधाई! यह ऐतिहासिक जीत टीम के असाधारण साहस, अनुशासन और जुनून को दर्शाती है। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए गर्व का क्षण है और वहां के बढ़ते खेल प्रेम और प्रतिभा को उजागर करता है। आशा है कि यह उपलब्धि कई युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और अधिक खेलने के लिए प्रेरित करेगी।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कर्नाटक के खिलाफ ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफी जीत के लिए जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। सिन्हा ने इस उपलब्धि को केंद्र शासित प्रदेश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के असाधारण प्रदर्शन और समर्पण की सराहना की। सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी टूर्नामेंट में बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है। टीम को मेरी शुभकामनाएं।

X पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का गौरवशाली क्षण आ गया है! हमारी क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतते हुए देखकर मेरी भावनाएं शब्दों से परे उमड़ रही हैं। उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास रचा- पूरे केंद्र शासित प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद, हम गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। आपने इतिहास को अमर कर दिया है - इसे सम्मान के साथ अपनाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई खेल क्रांति के लिए आभारी हूं। सभी युवाओं से- इस जोश को अपने क्षितिज को प्रज्वलित करने दें- अथक और लगन से प्रशिक्षण लें। इस जीत को आधार बनाकर प्रभुत्व के युगों का नेतृत्व करें - जम्मू-कश्मीर का अजेय भविष्य आपसे शुरू होता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में जीत के बाद जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम को बधाई दी और इसे दृढ़ता और लगन का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया। पारस डोगरा के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर टीम ने 67 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए मजबूत टीम कर्नाटक को हराया। अपने पहले रणजी फाइनल में खेलते हुए, जम्मू और कश्मीर ने पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त के दम पर खिताब जीता। यह बढ़त आठ बार की चैंपियन कर्नाटक टीम के लिए नामुमकिन साबित हुई, जिसकी कप्तानी देवदत्त पडिक्कल कर रहे थे। शाह ने अपने खाते पर न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम की सराहना की।

उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर की

भारतीय टीम को उनके दृढ़ संकल्प और लगन की अद्भुत कहानी के लिए हार्दिक बधाई। खिलाड़ी प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के कोचिंग स्टाफ, प्रबंधन और प्रशासकों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम किया है। मुझे विश्वास है कि यह जीत इस क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी के दिलों में आत्मविश्वास जगाएगी और आने वाली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा खेल दुनिया भर में प्रेरणा की ऐसी कहानियों से समृद्ध है, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को भी उतना ही सम्मान मिलेगा।

फाफ डु प्लेसिस ने किया 2026 विश्व कप फाइनल का बड़ा प्रिडिक्शन

नई दिल्ली। टीम इंडिया ने टी-20 विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को अब भी बरकरार रखा है। सुपर-8 चरण में साउथ अफ्रीका से पहला मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया पर उठ रहे सवाल अब इस जीत के साथ तारीफों में बदल गए हैं। अगर भारत अपने अगले मुकाबले में वेस्टइंडीज को मात दे देता है, तो उसके लिए सेमीफाइनल का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। वहीं, ग्रुप की अंकतालिका में दक्षिण अफ्रीका लगातार दो जीत के साथ और जिम्बाब्वे की दो हार के चलते पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बात करते हुए भविष्यवाणी की कि टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फाफ ने कहा, 'भारत बेहद मजबूत टीम है और अपनी सरज़मीन पर कभी कमजोर नहीं पड़ती।' उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार इस बार दक्षिण अफ्रीका फाइनल जीतकर पहली बार विश्व चैंपियन बनेगा। फाफ ने मज़ाकिया अंदाज में यह भी कहा कि फाइनल में डेविड मिलर बिलकुल वैसा ही कैच लेंगे जैसा सूर्यकुमार यादव ने टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में लिया था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

स्पेसएक्स क्रू-11 की समय से पहले वापसी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन की समय से पहले वापसी को लेकर जानकारी दी है। अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके ने बताया कि 7 जनवरी को अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्हें स्वास्थ्य समस्या हुई, इसके बाद सभी चार सदस्यों को निर्धारित समय से पहले लौटाने का फैसला किया। नासा के अनुसार यह आपात स्थिति नहीं थी, बल्कि उन्नत मेडिकल जांच के लिए कदम था। क्रू-11 का कैप्सूल 15 जनवरी को सैन डिएगो तट के पास सुरक्षित उतरा और साढ़े पांच माह का मिशन पूरा हुआ।

पेंटागन ने ज्वाइंट स्टाफ निदेशक पद से वाइस एडमिरल को हटाया

पेंटागन, एजेंसी। पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल फ्रेड कैचर को ज्वाइंट स्टाफ के निदेशक पद से हटा दिया है। कैचर ने दिसंबर में ही यह पद संभाला था। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि काचर अब अमेरिकी नौसेना में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन हटाने का कारण नहीं बताया। सूत्रों के अनुसार वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गए, हालांकि किसी विशेष वजह का खुलासा नहीं हुआ। डेन केन ने उनके योगदान की सराहना की। कैचर इससे पहले जापान स्थित अमेरिकी सातवें बेड़े के कमांडर और यूएस नेवल अकादमी के प्रमुख रह चुके हैं।

अमेरिका : रिटायर्ड पायलट ने चीन में दी ट्रेनिंग, गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पूर्व अमेरिकी वायु सेना के एलीट फाइटर पायलट और एफ-35 प्रशिक्षक गेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर को चीनी सैन्य पायलटों को गुप्त रूप से लड़ाकू प्रशिक्षण देने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजेनबर्ग ने कहा, अमेरिकी वायु सेना ने मेजर ब्राउन को एक विशिष्ट लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया था और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। एजेंसी 2023 में ब्राउन ने चीन जाकर दिया प्रशिक्षण...ब्राउन के सैन्य करियर में संवेदनशील इकाइयों का नेतृत्व, युद्ध अभियानों का संचालन और एफ-4, एफ-15, एफ-16, ए-10 तथा एफ-35 जैसे विमानों पर लड़ाकू पायलट एवं सिम्युलेटर प्रशिक्षक के रूप में सेवा शामिल थी।

हांगकांग कोर्ट ने जिमी लाई की धोखाधड़ी में मिली सजा रद्द की

विक्टोरिया, एजेंसी। हागकांग की अपीलीय अदालत ने पूर्व मीडिया कारोबारी जिमी लाई को राहत देते हुए उनकी धोखाधड़ी मामले में सजा रद्द कर दी। 78 वर्षीय लाई ने बंद हो चुके अखबार एपल डेली की स्थापना की थी और वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं। हालांकि, उन्हें हाल ही में चीन की ओर से लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक अन्य मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है, इसलिए वे जेल में ही रहेंगे।

आईएमएफ ने कहा- अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत

वाशिंगटन, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल फंड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि 2026 में वृद्धि दर बढ़कर 2.4 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो 2025 के 2.2 फीसदी से अधिक होगी। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि बेरोजगारी दर 4.5 फीसदी से घटकर 4.1 फीसदी हो सकती है और महंगाई 2027 तक फेडरल रिजर्व के दो फीसदी लक्ष्य तक आ सकती है।

सूडान के दारफुर में हिंसा

दारफुर , एजेंसी। सूडान के दारफुर क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों के एक समूह के अनुसार, हालिया हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई और 39 घायल हुए। तीन हजार से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। ज्यादातर विस्थापित महिलाएं और गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके पास न भोजन है न ही आश्रय।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा की गिरफ्तारी

न्यूयॉर्क , एजेंसी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा एली आघायेवा को इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में लिया। अधिकारियों ने अपार्टमेंट में प्रवेश के लिए 'लापता व्यक्ति' की तलाश का बहाना बनाया। छात्रा के वकीलों का दावा है कि बिना वारंट गिरफ्तारी की गई। बाद में न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात के बाद छात्रा को रिहा करने पर सहमति बनी। यह मामला अमेरिका में सख्त हो रही इमिग्रेशन नीति पर नई बहस छेड़ रहा है।

आरोप- बांग्लादेश सरकार ने डिफाल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफाल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है, जो देश में भीड़तंत्र की शुरुआत जैसा है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जमात ए इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पीएम की शह पर लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले सरकार ने अहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया था, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने नियुक्त किया था। मंसूर ने कहा कि उन्होंने न इस्तीफा दिया और न ही उन्हें हटाए जाने की कोई आधिकारिक सूचना मिली। उन्हें यह खबर मीडिया के जरिए पता चली।

गारमेंट कारोबारी रहे हैं मोस्ताकुर रहमान : मोस्ताकुर रहमान की नियुक्ति इसलिए अलग मानी जा रही है क्योंकि अब तक बांग्लादेश में केंद्रीय बैंक का गवर्नर आमतौर पर अनुभवी बैंकर, अर्थशास्त्री या वरिष्ठ सिविल सेवक होते रहे हैं। मोस्ताकुर एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और गारमेंट कारोबारी हैं। वे हेरा स्वेटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और

विपक्ष बोला- ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश में भीड़तंत्र चल रहा

हालिया चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति से भी जुड़े रहे थे। उनकी नियुक्ति को लेकर कर्ज चुकाने से जुड़े पुराने मामलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीडी न्यूज24 की रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी कंपनी 86 करोड़ टका का कर्ज समय पर नहीं चुका पाई थी। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि जो इंसान अपनी ही कंपनी के लिए स्पेशल कंडीशन पर कर्ज का पुनर्गठन कराता है, वह देश के बैंकिंग सिस्टम के हितों की रक्षा कैसे करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के पूर्व प्रोफेसर दीन इस्लाम ने भी कहा कि किसी एक्टिव कारोबारी को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाना गलत संदेश देता है और इससे हितों के टकराव की आशंका बढ़ती है।

विपक्ष ने मोस्तकुर को गवर्नर बनाने पर विरोध जताया : मोस्ताकुर की नियुक्ति के बाद विपक्षी नेता शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि बांग्लादेश बैंक में जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किसी को भी गवर्नर और उनके सलाहकारों जैसे सम्मानित लोगों को इस तरह अपमानित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से कई समस्याओं से जूझ रही है, तब बांग्लादेश बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था में इस तरह की कार्रवाई बची हुई अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर देगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों से विरोध करने की अपील की और कहा कि अगर सरकार सच में लोकतांत्रिक और भेदभाव-रहित बांग्लादेश बनाना चाहती है तो ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए। जरूरी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक निष्ठा के आधार पर।

अहसान हबीब को गवर्नर पद से हटाने का विरोध : विवाद की दूसरी बड़ी वजह उनकी नियुक्ति की परिस्थितियां हैं। अहसान हबीब मंसूर 2024 में चार साल के लिए गवर्नर बनाया गया था और उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक था, लेकिन 18 महीने से भी कम समय में ही उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। मंसूर को हटाए जाने से पहले कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि, मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को साजिश बताया था।

अहसान हबीब मंसूर की बर्खास्तगी से देश में कई लोग हैरान हैं। उन्हें 27 साल का अनुभव है। वे आईएमएफ जैसी संस्थाओं में काम कर चुके हैं। 2024 में शेख हसीना और उनकी अवामी लीग सरकार के हटने के बाद जब देश में आर्थिक अस्थिरता थी, तब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। जब उन्होंने पद संभाला था तब फॉरेन करेंसी रिजर्व 26 अरब डॉलर था। उनके पद छोड़ने तक यह बढ़कर 35 अरब डॉलर हो गया। उन्होंने टका को 122.20 प्रति डॉलर पर स्थिर किया और महंगाई दर को 2024 के 10.49% से घटाकर जनवरी 2026 में 8.58% तक लाने के लिए पॉलिसी अपनाई।

जिनेवा में यूएस-ईरान परमाणु वार्ता हुई पूरी, पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़े से युद्ध की आशंका

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकीं थी, क्योंकि इसी के साथ पश्चिम एशिया में सैन्य हलचल भी तेज हो गई है। वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना और संभावित युद्ध को टालना बताया गया है, जबकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने विमान और युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात कर रहा है।

युद्ध टालने की कोशिश, लेकिन खतरा बरकरार : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जिनेवा रवाना होने से पहले चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। उन्होंने कहा यह किसी के लिए जीत की स्थिति नहीं होगी। पूरा क्षेत्र एक विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ सकता है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वह इस्त्राइल को भी निशाना बना सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।

पिछले साल युद्ध से टूटी थी बातचीत : पिछले वर्ष कई दौर की वार्ता उस समय पटरी से उतर गई थी जब इस्त्राइल ने ईरान पर 12 दिन तक हमले किए और अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की। हालांकि नुकसान की पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान फिलहाल यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा, लेकिन वह उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश में है जहां से परमाणु हथियार बनाना संभव हो सके।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी सैन्य हलचल : उधर, अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के जहाजों की गतिविधियों में भी बदलाव देखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे से कई पोत समुद्र में तैनात किए गए हैं। तेल बाजार भी इस तनाव से प्रभावित है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पिछली वार्ता के दौरान ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही अस्थायी रूप से रोकने का संकेत दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ा था।

किम जोंग-उन की साउथ कोरिया को चेतावनी, बोले- खतरा हुआ तो 'पूरी तरह तबाह' कर देंगे

प्योंगयांग, एजेंसी। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग-उन ने साउथ कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। किम ने कहा है कि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे साउथ कोरिया को 'पूरी तरह नष्ट' कर सकते हैं। प्योंगयांग में सात दिन चली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के समापन पर किम ने अगले पांच वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु-संचालित पनडुब्बी, एआई-युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम ने साउथ कोरिया को 'स्थायी दुश्मन' बताते हुए कहा कि उससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि प्रतिबंध और दबाव की नीति छोड़े तो संवाद संभव है। कांग्रेस के बाद राजधानी में भव्य सैन्य परेड आयोजित की गई, जिसमें किम अपनी बेटी के साथ नजर आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम

एक ओर अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भविष्य की संभावित बातचीत के लिए विकल्प भी खुले रख रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की जांचकर्ता पर अमेरिकी प्रतिबंध : वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार जांचकर्ता फ्रांसेस्का अल्बानीज के परिवार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि इस्त्राइल की आलोचना करने पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हैं। अल्बानीज ने गाजा में इजराइली कार्रवाई को 'जनसंहार' बताया था, जिसे अमेरिका और इस्त्राइल ने खारिज किया। परिवार का कहना है कि प्रतिबंधों से उनका निजी और पेशेवर जीवन प्रभावित हुआ है।

'जो होना है, वह हमने बता दिया', यूरेनियम संवर्धन पर ईरानी विदेश मंत्री अराघची की अमेरिका को दो टूक

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान जिनेवा में दोनों देशों ने वार्ता की। कई घंटों की बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यह गहरी चिंता भरी लंबी बातचीतों में से एक है। जिनेवा में अब तक हुई इन चर्चाओं के बाद कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आशंका बनी हुई है। अब्बास अराघची ने गुरुवार को ईरानी सरकारी टीवी से बातचीत में कहा कि जो कुछ होना है, वह हमारी ओर से साफ कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने बातचीत के विवरण साझा नहीं किए। अमेरिकी पक्ष की ओर से भी तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई और व्हाइट हाउस ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी।

अगले हफ्ते फिर होगी अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत जिनेवा में हुई कई घंटों की अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने कहा कि बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, उन्होंने भी विस्तार से जानकारी नहीं दी। आगे की वार्ता का दौर अगले सप्ताह वियना में होगा, जहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। वार्ता समाप्त होने से ठीक पहले ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के अपने अधिकार पर अडिग है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। यह रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों से अलग माना जा रहा है। ट्रंप की मांग है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन, लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रोके। इसके साथ ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना बंद करे। वहीं, ईरान का कहना है कि वह केवल परमाणु मुद्दे पर बात करेगा। अराघची ने फिर दी चेतावनी अराघची ने एक साक्षात्कार में फिर से चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध लक्ष्य माने जाएंगे और इससे व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने इसे बहुत डरावना बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में किसी की जीत नहीं होगी।

'अमेरिका के लिए बड़ी जीत', व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर कोर्ट की हरी झंडी के बाद गदगद ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संघीय जज के फैसले का स्वागत किया है। जज ने व्हाइट हाउस में बन रहे नए बॉलरूम (विशाल हॉल) के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद ट्रंप ने इसे 'अमेरिका के लिए शानदार खबर' बताया।

संरक्षण समूहों की मांग जज ने की खारिज : यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ संरक्षण समूहों ने अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि व्हाइट हाउस में इतना बड़ा निर्माण करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी, स्वतंत्र समीक्षा और आम जनता से राय लेने जैसी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं। उन्होंने अदालत से निर्माण

कार्य रोकने की मांग की थी। लेकिन जज ने उनकी मांग खारिज कर दी।

जज के फैसले के बाद गदगद दिखे ट्रंप : फैसले के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर कहा कि यह दुनिया का सबसे सुंदर बॉलरूम होगा। उन्होंने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट में एक भी डॉलर टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं लग रहा है। उनके मुताबिक पूरा खर्च 'देशभक्त दानदाताओं' और निजी योगदान से उठाया जा रहा है।

क्या है व्हाइट हाउस का बॉलरूम प्रोजेक्ट : यह बॉलरूम करीब 90,000 वर्ग फुट का होगा। इसका उपयोग भविष्य में शपथ ग्रहण समारोह, बड़े स्टेट विजिट, राजकीय भोज और बड़े कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

निजी दान से आ रहा पूरा पैसा- ट्रंप प्रशासन : इस निर्माण के लिए पहले अनुमानित लागत 200 मिलियन डॉलर (1,820 करोड़ रुपए) बताई गई थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 300 मिलियन डॉलर (2,730 करोड़ रुपए) हो गई है। प्रशासन का कहना है कि पूरा पैसा निजी दान से आ रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी संरचना व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक पहचान को बदल देगी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो यह ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में किया गया सबसे बड़ा भौतिक बदलाव माना जाएगा।

अफगानिस्तान के नये कानून पर यूएन ने जताई गंभीर चिंता

एथेंस, एजेंसी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने नया दंड संहिता लागू किया है। इस कानून पर जनवरी में वहां के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने हस्ताक्षर किए थे। इस नए कानून में कुल 119 धाराएं हैं और इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

पत्नी को पीटने पर सिर्फ 15 दिन की सजा : सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में पत्नी को पीटने पर सजा सिर्फ 15 दिन की जेल रखी गई है, वह भी तब जब पत्नी अदालत में साबित कर दे कि उसे चोट लगी है और शरीर पर कट, घाव या नीला निशान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपने मायके चली जाती है और वहां रुकती है, तो उसे तीन महीने की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसके मायके वाले उसे वापस पति के पास नहीं भेजते, तो उन्हें भी सजा दी जा सकती है।

यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ- तुर्क : संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और महिलाओं के साथ भेदभाव को कानूनी रूप देता है। यूएन वुमेन की प्रतिनिधि सुसान फर्गूसन ने भी कहा कि इस कानून से पुरुषों को महिलाओं पर अधिकार की स्थिति में रखा गया है और महिलाओं के लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाएगा। इस कानून में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जानवरों को लड़ाने पर पांच महीने तक की जेल हो सकती है। अफगानिस्तान में मुर्गों और तीतरों की लड़ाई एक आम परंपरा रही है, लेकिन तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद इस पर रोक लगा दी थी। अब नए कानून में जानवरों की लड़ाई की सजा पत्नी को गंभीर रूप से पीटने की सजा से कहीं ज्यादा है।

एक ही अपराध के लिए अलग सजा : सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लोगों को अलग सजा दी जाएगी। धार्मिक विद्वानों और बड़े लोगों को सिर्फ चेतावनी दी जा सकती है, जबकि आम लोगों को जेल और निचले वर्ग के लोगों को शारीरिक सजा दी जा सकती है। हालांकि हत्या के मामलों में यह फर्क नहीं होगा और दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। पैगंबर मोहम्मद का अपमान भी मौत की सजा वाला अपराध है, हालांकि पश्चाताप करने पर इसे छह साल की जेल में बदला जा सकता है।

पाकिस्तान की सेना हमलावरों को नेस्तनाबूत करने में सक्षमः शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया है। पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदल लेने के लिए अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन के इलाके में हमला किया तो पाकिस्तान ने सीधा राजधानी काबुल को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने काबुल की 12 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान ने इसे आतंकी हमला बताया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना हमलावरों को नेस्तनाबूत करने में सक्षम है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सेनाओं के पास हमलावरों को कुचलने की ताकत है। इस स्थिति में पूरा देश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के काबुल और दो अन्य प्रांतों में हवाई हले किए हैं। ऐसे में अब कतर की मध्यस्थता में कराया गया युद्धविराम कमजोर हो गया है।

काबुल में तीन विस्फोट : काबुल में कम से कम तीन विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजधानी में हमले कहां हुए और इनमें किसी के हताहत होने की जानकारी भी तुरंत नहीं मिल सकी। सरकारी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने दक्षिण में कंधार और दक्षिण-पूर्वी प्रांत पकतिया में भी हवाई हमले किए।

पाक ने अफगानिस्तान पर लगाए बिना उकसावे के हमले के आरोप : मुजाहिद ने बृहस्पतिवार रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पाकिस्तानी सेना के बार-बार विद्रोह और हमलों के जवाब में डूरंड रेखा के पास स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए।'' अफगान रक्षा मंत्रालय ने

कहा कि जवाबी हमले सीमा से लगे छह प्रांतों में किए गए। दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है, जिसे अफगानिस्तान औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता।

यूएन ने भी संघर्ष पर जताई चिंता : इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सीमा पार झड़पों की खबरों पर चिंता जताई। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने दोनों पक्षों से मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाने की अपील की है। दोनों देशों ने हताहतों के अलग-अलग आंकड़े दिए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें से कुछ के शव अफगानिस्तान ले जाए गए, जबकि ''कई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया।'' मंत्रालय के अनुसार, अफगानिस्तान के आठ सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए और तीन घायल हुए हैं, जबकि 36 अफगान लड़ाके मारे गए। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों में सैनिकों, नागरिकों और संदिग्ध आतंकियों की मौत हुई थी। हालांकि, कतर की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम काफी हद तक लागू रहा लेकिन सीमा पर बीच-बीच में गोलीबारी होती रही है। नवंबर में हुई कई दौर की शांति वार्ताएं भी किसी औपचारिक समझौते पर नहीं पहुंच सकीं।

आईआरएस द्वारा गोपनीय जानकारी साझा करने पर अदालत की टिप्पणी : वाशिंगटन, एजेंसी। एक अमेरिकी जज ने कहा है कि टैक्स विभाग आईआरएस ने लगभग 42,695 बार गोपनीय करदाता जानकारी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई के साथ साझा कर कानून तोड़ा। अदालत के अनुसार, बिना उचित कानूनी आधार के पतों की जानकारी दी गई। सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल अदालत ने इसे गोपनीयता कानून का उल्लंघन माना है।

स्विस बैंक पर अमेरिकी कार्रवाई : वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने एक छोटे स्विस बैंक पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। आरोप है कि बैंक ने ईरान और रूस से जुड़े लोगों के 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा धन को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के जरिए स्थानांतरित किया। ट्रेजरी विभाग का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एनसीआर में 1 मार्च से तेज सतही हवाएं चलेंगी, बढ़ेगा तापमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। एनसीआर में मौसम स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि 1 मार्च से दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और दिन में गर्मी का अहसास होने लगेगा। आईएमडी की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सुबह वातावरण में हल्की धुंध छाई रही। वहीं 1 मार्च को भी अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की धुंध रहने की संभावना है। आर्द्रता का स्तर अधिकतम 80 फीसदी और न्यूनतम 30 फीसदी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मार्च को भी अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी। इधर, एनसीआर में एक्यूआई में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 255, सेक्टर-1 में 205, सेक्टर-62 में 182 और सेक्टर-116 में 304 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 315, इंदिरापुरम में 276, वसुंधरा में 233 और संजय नगर में 200 रहा। दिल्ली के आनंद विहार में 332, चांदनी चौक में 276, बवाना में 244, अशोक विहार में 237 और अलीपुर में 219 दर्ज किया गया। कई क्षेत्रों में यह 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में तेज धूप के कारण लोगों को अब हल्की गर्मी का अहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आगामी दिनों में क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि 1 मार्च से चलने वाली तेज हवाएं प्रदूषण के स्तर को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती हैं।

कुरुक्षेत्र जिले के सरकारी स्कूल डेस्क की भारी कमी... जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे

कुरक्षेत्र (एजेंसी)। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सरकारी स्कूल इन दिनों डेस्क की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बालवाटिका से लेकर बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पर्याप्त डेस्क न मिलने के कारण फर्श पर बैठना पड़ रहा है। कई स्कूलों में 10 से 12 वर्ष पुराने डेस्क ही उपयोग में हैं, जिन्हें बार-बार मरम्मत कर चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग हर दो माह में स्कूलों से डेस्क की मांग संबंधी रिपोर्ट तो मांग लेता है, लेकिन आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने एमआईएस पोर्टल पर गूगल फॉर्म के माध्यम से फिर डिमांड मांगी है। आंकड़ों के अनुसार जिले के करीब 779 स्कूलों में कुल 5594 डेस्क की आवश्यकता है। इसमें बालवाटिका से पांचवीं तक 2269, छठी से आठवीं तक 1726, नौवीं से बारहवीं तक 767 तथा ग्यारहवीं-बारहवीं के लिए 832 डेस्क की जरूरत बताई गई है। सबसे अधिक समस्या प्राथमिक विद्यालयों में है, जहां करीब 50 प्रतिशत स्कूलों में डेस्क का अभाव है। छोटे बच्चों को टाट-दरी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। गांव थाना के राजकीय प्राइमरी स्कूल में 184 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और वहां 80 डेस्क की मांग भेजी गई है। उपलब्ध डेस्क को मरम्मत कर उपयोग किया जा रहा है। हरियाणा प्राइमरी हेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाने की बात करती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक के अनुसार स्कूलों से ड्यूल डेस्क का डाटा प्राप्त हो चुका है और टीमें सत्यापन के लिए निरीक्षण करेंगी।

अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरित राहत, खुश होकर बोले बटुक... हम अपने गुरु पर पूरा भरोसा

वाराणसी(एजेंसी)। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दो बटुकों से कथित यौन शोषण के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में तय की है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वाराणसी स्थित श्री विदया मठ में उत्साह का माहौल देखा गया। मठ में अध्ययनरत करीब 400 बटुक वेद, धर्म और आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई बटुकों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताकर अपने गुरु के प्रति विश्वास व्यक्त किया। उनका कहना है कि उन्हें अपने गुरु पर पूरा भरोसा है और उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। उन्होंने न्यायपालिका पर आस्था जताकर कहा कि सत्य अंततः सामने आएगा। गौरतलब है कि दो बटुकों की शिकायत के आधार पर शंकराचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह प्रकरण चर्चा में आया। हालांकि, अदालत द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद मठ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियां पूर्ववत जारी हैं। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है और किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। कानूनी जानकारों के अनुसार, अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में होगा। तब तक सभी पक्ष अदालत के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और काशी के धार्मिक व सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा जारी है।

उत्तरप्रदेश में मोदी-योगी छाप पिचकारियां की धूम

लखनऊ (एजेंसी)। 2027 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले होली से माहौल बन रहा है। लखनऊ की दुकानों में पिचकारियां आ गई हैं। इसमें मोदी-योगी छाप और धनुष-बाण छाप पिचकारी की धूम है। गुलाल वाले पटाखे भी आ गए हैं। बच्चों को ये सभी पिचकारियां भा रही हैं। होली की पिचकारी पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ 'हिंदुस्तान की बोली-घर-घर होली' जैसे स्लोगन प्रिंट हैं। पिचकारी में पीएम मोदी, ब्रह्मोस, कुल्हाड़ी, हथौड़ा और म्यूजिकल ट्रेंड में हैं। इसके अलावा ऐसी सफेद टीशर्ट आई है जो पानी पड़ते ही रंगीन हो जाएगी। होली के इस खास मौके पर सर्राफा मार्केट भी चहक रहा है। चांदी से बनी पिचकारी, बाल्टी, लड्डू गोपाल, काजू कतली और लड्डू खूब चर्चा में हैं। इस होली पर दिवाली का फील देने के लिए कलर पटाखे लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। रंगीन विग के साथ अलग-अलग डिजाइन के फेस मास्क मार्केट में आए हैं। कुल्हड़ अनार, 5 से लेकर 16 शॉट वाला स्मोक पटाखा मिल रहा है। इसके साथ ही तीन फ्लेवर वाला आइसक्रीम पटाखा लोगों को खूब भा रहा है, जिसमें से वैनिला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के तीन रंगों के साथ खुशबू भी फूटती है।

अब ईरान-अमेरिका जंग पर कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल... क्या वे इस युद्ध का समर्थन करते हैं?

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच कई दिनों से जारी तनाव के बाद आखिरकार इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान के साथ-साथ इजरायल में भी कई जगह पर विस्फोट होने की खबर है। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर भारत की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में इजरायल की यात्रा करके लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने हमला बोलकर पूछा है कि क्या पीएम मोदी इजरायल और ईरान के बीच में जारी युद्ध का समर्थन करते हैं?

कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला बोल दिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से

लौटने के बमुश्किल दो दिन के बाद हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में तमाम दिखावे के बाद, पीएम मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का उपयोग इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वे इस युद्ध का समर्थन करते हैं?

गौरलतब है कि प्रधानमतंत्री मोदी दो दिन के इजरायल के दौरे पर थे। इस दौरे पर भारत और इजरायल के बीच में कई अहम समझौते हुए और पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया था। हालांकि, पीएम मोदी के इस दौरे से ईरान पर किए जा रहे हमले को कोई लेना-देना नहीं था। क्योंकि अमेरिका और इजरायल के बीच पीएम के दौरे के बहुत पहले से ही ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। जिनेवा में चल रही बातचीत के बीच जब ईरान, अमेरिकी की शर्तों पर खड़ा नहीं उतरा, इसके बाद इजरायल और यूएस ने मिलकर तेहरान के ऊपर हमला बोल दिया। मध्य-पूर्व में इस संकट के बादल पिछले कई महीनों से मंडरा रहे थे।

कश्मीर के बड़गाम में शिया मुस्लिमों ने ईरान के समर्थन में और अमेरिका-इजरायल के विरोध में प्रदर्शन किया

नई दिल्ली। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को लेकर भारत में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत में शिया मुस्लिम संगठनों ने इस हमले की निंदा की है। कश्मीर के बड़गाम में शिया मुस्लिमों ने खामेनेई के बड़े-बड़े पोस्टरों के साथ ईरान के समर्थन में और अमेरिका-इजरायल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शिया धर्मगुरुओं ने भी इस हमले की निंदा की है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि जिस तरीके से इजरायल ने ईरान पर हमला किया है वो अफसोसजनक है। रमजान का महीना चल रहा है। जिस महीने में जंगें रोक दी जाती हैं, उस महीने में ये काफीर और शातिर इजरायल ने जिस तरीके से हमला किया है, अब इजरायल और अमेरिका को ईरान के पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। खाड़ी के अंदर अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, उन्हें तबाह कर देगा। पहले भी खामेनेई साब ने अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और ट्रंप को सीजफायर करना पड़ा था।

एआई समिट मामला : यूथ कांग्रेस के चीफ चिब को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

-पुलिस नहीं बता पाई पर्याप्त ठोस कारण, कांग्रेस ने ली राहत की सांस

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शनिवार को जमानत दे दी। यह मामला 20 फरवरी को भारत एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सात दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि पुलिस पर्याप्त ठोस कारण नहीं बता पाई। रिपोर्ट के मुताबिक जमानत पर चिब को 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। साथ ही अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में सरेंडर करने होंगे। उनके वकील ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि रिमांड बढ़ाने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है। पुलिस का आरोप है कि चिब इस प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता थे। 20 फरवरी को एआई समिट के आखिरी दिन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। इनमें पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ स्लोगन शामिल थे। पुलिस का कहना है कि चिब ने कृष्णा हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव समेत अन्य के साथ मिलकर गैरकानूनी जमावड़ा किया, पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी में बाधा डाली और हमला किया। साथ ही पूछताछ में सहयोग नहीं किया और फरार आरोपियों व टी-शर्ट छपवाने के स्रोत की जानकारी नहीं दी। चिब को 24 फरवरी को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार रात देर से कोर्ट में रिमांड एक्सटेंशन मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दी। इस घटना ने बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा किया। बीजेपी ने इसे भारत की ग्लोबल इमेज खराब करने की साजिश बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे युवाओं की बेरोजगारी और एआई से नौकरियां छिनने जैसी चिंताओं को दिखाने वाला शांतिपूर्ण विरोध बताया। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने भी 'शर्टलेस' तरीके की आलोचना की। अब जांच जारी है, लेकिन चिब की जमानत से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है।

अगर फैसला गलत लिया जाता है तो सही करने ऊपरी अदालतें होती हैं

-केजरीवाल-सिसोदिया के शराब घोटाले में बरी होने पर रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया

धर्मशाला (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर कहा कि अगर फैसला गलत लिया जाता है तो उसको सही करने के लिए ऊपरी अदालतें होती हैं। रिजिजू शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। यहां केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। निचली अदालत के फैसले में अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके सुधार के लिए ऊपरी अदालत में मामले को ले जाया जाता है। गलत फैसला दिया गया या अगर तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की गई, तो ऊपरी अदालत में अपील फाइल की जा सकती है, जहां से सही फैसला लिया जाता है। इसी बीच किरेन रिजिजू ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि मुझे मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है और जिसमें कुछ तार जुड़े हुए हैं। हालांकि, मैं अभी गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा हूं, इसलिए मुझे इस मामले की

पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मामला है, उसे सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहां आता रहता हूं। इस बार चंबा साइट के क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट हैं, जो उनके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। उन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का कार्य जारी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले समय मैंने लाहौल-स्पीति का दौरा किया था। वहां भी मंत्रालय की ओर से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिलहाल, वे चंबा का दौरा करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगे।

राज्यसभा चुनाव: टीएमसी ने चार उम्मीदवारों के नामों का किया एलान, बाबुल सुप्रियो को मौका

कोलकाता (एजेंसी)। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल से उच्च सदन के लिए अपने चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार अपने चयन में राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक कुशलता, कानूनी विशेषज्ञता और सांस्कृतिक लोकप्रियता का एक अनूठा संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सूची को साझा करते हुए विश्वास जताया कि ये उम्मीदवार पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और हर भारतीय के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए संसद में आवाज उठाएंगे।पार्टी द्वारा घोषित नामों में सबसे प्रमुख नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का है, जो पहले भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

सितंबर 2021 में भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने अब

उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इनके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व महानिदेशक राजीव कुमार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। प्रशासनिक गलियारों में अपनी धाक रखने वाले राजीव कुमार के अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कानूनी मोर्चे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी पर भरोसा जताया है, जो देश के कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। वहीं, ग्लैमर और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को जोड़ते हुए टॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री कोएल मलिक को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। कोएल मलिक की जमीनी लोकप्रियता पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संचार कर सकती है।

हालांकि, इस घोषणा के साथ ही पार्टी के भीतर बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। टीएमसी ने अपने उन चार सांसदों को दोबारा नामांकित नहीं किया है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें महासचिव सुब्रत बख्शी, रितब्रत बनर्जी और साकेत गोखले शामिल हैं, जबकि मौसम नूर पहले ही कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। इस बीच, विपक्षी दल भाजपा ने इन उम्मीदवारों के चयन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा की बंगाल इकाई ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की बंगाल पहले वाली नीति महज एक दिखावा है, क्योंकि घोषित उम्मीदवारों में से आधे गैर-बंगाली हैं। भाजपा का दावा है कि टीएमसी केवल चुनावी लाभ के लिए बंगाली अस्मिता का इस्तेमाल करती है और असल में बंगालियों को नजरअंदाज कर रही है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। यह चुनाव परिणाम राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे।

अब यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो कटेंगे अंक, रद्द होगा लाइसेंस

-सरकार ग्रेड-आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की बना रही योजना

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार अब ग्रेड-आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल करीब 1.8 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में जाने या नशे में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है।

दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन में गडकरी ने गुरुवार को कहा कि लोगों का जीवन अत्यंत अहम है और सरकार सड़क सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने बताया कि सरकार पहले ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस में 'ग्रेडेड अंक प्रणाली'

ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.8 लाख लोगों की जान जाती है।

उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से 72 फीसदी 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोग हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 10,119 लोगों की दुर्घटनाओं में जान गई। हेलमेटय नहीं पहनने से 54,122, सीट बेल्ट नहीं लगाने से 14,466 जबकि तेज रफ्तार के कारण 1.2 लाख लोगों की जान गई। अन्य प्रमुख कारणों में गलत दिशा में व नशे में वाहन चलाना और मोबाइल फोन पर बात करना शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की है कि वे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें और उपचार खर्च या कानूनी औपचारिकताओं की चिंता न करें। पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता प्रणाली उपलब्ध है। योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना के शिकार को हादसे की तारीख से सात दिन तक 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा।

ग्रेड-आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली में तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना और शराब पीकर गाड़ी चलाना जैसे अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुछ अंक काटे जाएंगे। यदि सभी अंक समाप्त हो जाते हैं तो दोषी का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है या अपराध दोहराने पर रद्द भी किया जा सकता है।

ओडिशा में युवती के साथ रेप के बाद चौथी मंजिल से फेंका, प्रेमी और मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जगतसिंहपुर (एजेंसी)। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में एक 23 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी और हत्या का एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के सिलसिले में युवती के प्रेमी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर युवती को धोखा देने, उसके साथ बलात्कार करने और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे एक इमारत की चौथी मंजिल से नीचे फेंकने का गंभीर आरोप है। जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक अंकित कुमार वर्मा ने शुक्रवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए प्रेमी की उम्र 31 साल है, जबकि दूसरा मुख्य आरोपी 24 वर्षीय युवक है जो मूल रूप से झारखंड के धनबाद का निवासी है और पारादीप की एक निजी कंपनी में कार्यरत है।

पुलिस जांच के अनुसार इस दुखद घटनाक्रम की शुरुआत पिछले रविवार को हुई थी जब पीड़िता अपने प्रेमी के साथ विवाह करने के उद्देश्य से तिरतोल

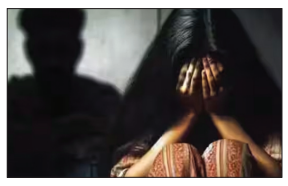

स्थित एक मंदिर गई थी, लेकिन वहां उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर धोखा दे दिया और सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए युवती के साथ मारपीट की तथा उसे एक बस स्टैंड पर असहाय स्थिति में अकेला छोड़कर वहां से फरार हो गया। रविवार की शाम जब पीड़िता बस स्टैंड पर अकेली और परेशान खड़ी थी, तभी नशे में धुत झारखंड निवासी दूसरे आरोपी ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने का झांसा दिया। अनजान शहर में खुद को असुरक्षित पाकर युवती ने उस पर भरोसा कर लिया लेकिन आरोपी उसे सहायता देने के बजाय अपने किराए के मकान पर ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। जब पीड़िता ने इस हैवानियत के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई और आरोपी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, तो वह घबरा गया और पकड़े जाने के डर से उसने युवती को इमारत की चौथी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। सिर में गंभीर चोटें आने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और सोमवार तड़के उसका शव बरामद किया गया जिस पर चोट के कई गहरे निशान मौजूद थे। इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई जिसमें युवती को रविवार रात संदिग्ध आरोपी की इमारत में जाते हुए देखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवती के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है जिसके बाद पुलिस ने झारखंड निवासी आरोपी की मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। मृतका के भाई द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच जारी है।

अमेरिका-ईरान जंग में अगर बंद हुआ होर्मुज जलडमरूमध्य... तब तेल सप्लाई पर क्या करेगा भारत

-भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा गुजरता

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से कड़े संकेतों के बाद आशंका है कि यदि सैन्य टकराव होता हैं तब ईरान रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर सकता है।

यह वहीं समुद्री मार्ग है, जिससे होकर भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ÷ऑयल चोक पॉइंट÷ माना जाता है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा यहीं से गुजरता है। एशियाई देशों खासकर इंडिया और चीन के लिए यह जीवनरेखा है। अमेरिका की अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार, 2024-25 में प्रतिदिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस मार्ग से गुजरे है।

बात दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85-90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। खाड़ी देशों से आने वाला तेल मुख्य रूप से इसी मार्ग से गुजरता है। हालांकि रूस से आने वाला तेल होर्मुज से नहीं गुजरता, लेकिन खाड़ी सप्लाई रुकने से वैश्विक कीमतें उछल सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत के आयात बिल और महंगाई पर पड़ेगा।

अगर होर्मुज बंद होता हैं तब क्या होगा

इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। भले ही भारत को वैकल्पिक स्रोत मिल जाएं, लेकिन वैश्विक कीमतों में तेज उछाल तय माना जाता है। ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। इससे रुपये पर दबाव बढ़ेगा, चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है। इसके बाद ईंधन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स महंगे होगा, जिससे मंहगाई बढ़ेगी और आम जनता पर इसका सीधा असर होगा। युद्ध क्षेत्र घोषित होने पर जहाजों के बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ जाते हैं।

क्या विकल्प हैं भारत के पास?

सऊदी अमराको पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन (5 मिलियन बैरल/दिन क्षमता) चलाता है, जो लाल सागर तक जाती है। यूएई की 1.8 मिलियन बैरल/दिन क्षमता वाली पाइपलाइन फुजैराह तक तेल पहुंचाती है, जो होर्मुज को बाईपास करती है। लेकिन इनकी क्षमता सीमित है पूरी खाड़ी सप्लाई को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। भारत के पास आपातकालीन भंडार मौजूद हैं, जो कुछ हफ्तों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। भारत ने रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से आयात बढ़ाकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। यदि होर्मुज बाधित होता है, तब इसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक भी प्रभावित होगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी।